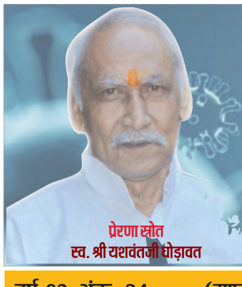

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-02, अंक - 34 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 28 मई 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

भारत-चीन सीमा विवाद पर ट्रंप बोले-अमेरिका मध्यस्थता को तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के सीमा विवाद में मध्यस्तथा की पेशकश की है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, 'हमने भारत और चीन को सूचित किया है कि अमेरिका मौजूदा सीमा विवाद के संबंध में मध्यस्थता के लिए तैयार और इच्छुक है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के बारे में भी कई बार मध्यस्थता की पेशकश की थी जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया था।

हाल के दिनों में लद्दाख और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हुई है। लद्दाख में एलएसी को लेकर विवाद दोनों पक्षों के बीच स्थानीय स्तर पर हुई सैन्य बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला है। सूत्रों के अनुसार चीनी सैनिकों ने एलएसी के भारतीय इलाके में घुसपैठ कर वहां टेंट लगा दिए हैं जिसका भारतीय सेना विरोध कर रही है। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं।

इस बीच नई दिल्ली में चीन के राजदूत सन विडोंग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि कोविड के खिलाफसाझा सहयोग से नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को सही नजरिये से देखना चाहिए। उन्हें अपने मतभेदों को व्यापक द्विपक्षीय सहयोग में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। भारत और चीन एक दूसरे के लिए अवसर पैदा करते हैं तथा वह एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं है। चीनी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के लोगों को भारत-चीन संबंधों के महत्व को समझना चाहिए तथा राष्ट्रपति शी जिंगपिंग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच कायम एक राय को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपस में रणनीतिक विश्वास बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मतभेदों को हल करने के लिए संपर्क और संवाद के जरिए हल करने पर भी जोर दिया।

पहले दो पत्नी के मध्य किए हिस्से, बाद में बेटों के मध्य बंटवारे की बात पर विवाद

परिजनों ने लगाए आरोप - पुलिस के सामने दबाव के चलते युवक ने कीटनाशक पीकर दी जान

माही की गूंज, खवासा। उमेश मालवीय

जिले में जर, जोरू व जमीन के ऐसे विवाद हैं कि विवादों में एक-दूसरे को काटते और मरते भी देखा गया है। पर समय के साथ ऐसे विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।

खवासा के समीपस्थ ग्राम पंचायत नरसिंगपाड़ा के निवासी भुंडा गणावा (60) की दो पत्नी है। बड़ी पत्नी भूला के 3 पुत्र तेरु, गुड्डू व राहुल तो वहीं छोटी पत्नी गोबरी के 2 पुत्र लक्ष्मण व कमलेश है। जानकारी अनुसार भुंडा ने छोटी पत्नी गोबरी से विवाह के बाद गांव के लोगों के मध्य संपत्ति का बटवारा दोनों पत्नी के मध्य किया था। जिसमें दोनों पत्नी को कितने भी पुत्र हो पर उसका हिस्सा उसकी मां के हिस्से में आए हिस्से में रहेगा। लंबा समय बीतने के बाद बड़ी पत्नी व उसके पुत्र व पिता की ओर से फिर से हिस्से को लेकर परिवार में चर्चा चली और दो पत्नी के बजाए पांच पुत्रों में हिस्सा हो जिस पर पारिवारिक विवाद चले। यानि बड़ी पत्नी के 3 पुत्र व छोटी पत्नी के 2 पुत्र होने के कारण छोटी पत्नी के हिस्से में दी गई जमीन का एक हिस्सा बड़ी पत्नी के पुत्र को देने की बात हुई, पर छोटी पत्नी गोबरी इस बात से अड़ी रही कि जो पूर्व में पति भुंडा ने दोनों पत्नी को कितने भी पुत्र हो पुत्र को मां के हिस्से में से ही बंटवारा होगा, इसलिए छोटी पत्नी किसी भी स्थिति में हिस्सा देने के लिए राजी नहीं हुई।

मृतक का भाई कमलेश

मृतक की बेहाल पत्नी

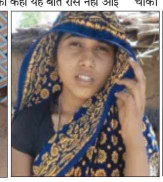

मृतक की पुत्री मोनू

मृतक की मां गोबरी

जानकारी अनुसार भुंडा ने बड़ी पत्नी के पुत्र तेरु के साथ छोटी पत्नी की कोख से जन्मे अपने ही पुत्र लक्ष्मण पर दबाव बनाने हेतु पुलिस चौकी में एक आवेदन दिया। पुलिस भी आपसी पारिवारिक विवाद में पंचायत के एक जनप्रतिनिधि के इशारे पर लक्ष्मण को लेने तेजपुरा पहुंच गई। घर पर लक्ष्मण नहीं मिला पर मां, पत्नी व उसकी छोटी बेटी मोनू मिली। पुलिस ने पुलिसिया पावर महिलाओं पर दिखाया तो लक्ष्मण की पुत्री ने कहा कि, मेरे पिता ने कोई गुनाह नहीं किया है, वह खवासा ही मजदूरी करने गया है। पुलिस को कही यह बात रास नहीं आई तो पुलिस ने लक्ष्मण की बेटी को ही दो झापड़ लगाने की बात कह दी। पुलिस के जाने के बाद मोनू ने अपने पिता को फोन कर पुलिस की पूरी हकीकत बताई। जिस पर लक्ष्मण 1 घंटे में ही घर पहुंच गया और लक्ष्मण के घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही संख्या बल बढ़ाकर पांच पुलिसकर्मी फिर से बिना किसी एफआईआर के ही गिरफ्तार करने की मंशा से लक्ष्मण के घर पहुंच गए। प्रधान आरक्षक व एएसआई ने पुलिस की गाड़ी में बैठ चलने का दबाव लक्ष्मण पर बनाया। जिस पर लक्ष्मण, मेरा ऐसा क्या गुनाह है जो मैं पुलिस चौकी पर आऊं और पुलिस के साथ हुई कहासुनी के साथ ही पुलिस के दबाव के कारण लक्ष्मण घर के अंदर गया और कीटनाशक दवाई लाकर पुलिस के सामने ही पी गया। मौके पर उपस्थित पुलिस उसे कीटनाशक दवाई पीने से भी नहीं रोक पाई, पर आनन-फानन में पुलिस हरकत में आ गई और लक्ष्मण को खवासा अस्पताल लेकर आई। खवासा से पेटलावद ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान लक्ष्मण (35) की मौत हो गई।

गूंज ने तेजपुरा जाकर हकीकत जानी तो, उक्त पूरा मामला मृतक लक्ष्मण के छोटे भाई कमलेश, मां गोबरी व बेटी मोनू ने बताया। उन्होंने कहा कि, परिवार व पुलिस के दबाव के कारण ही लक्ष्मण ने अपनी जान ले ली है। जब पूर्व में दो पत्नियों के बीच हिस्से हो गए थे तो वर्षो बाद फिर नए हिस्से की बात कहां से आई और बिना किसी अपराध व एफआईआर के पुलिस ने लक्ष्मण पर इतना दबाव क्यों बनाया कि, उसको आत्महत्या करनी पड़ी? आरोपों के साथ ही पीड़ित परिवार व बेहाल लक्ष्मण की पत्नी कमला ने मांग की है कि, लक्ष्मण की मौत में तेरु, भुंडा एवं परिवार के साथ पुलिस के विरुद्ध भी जांच की जाए। जिन्होंने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। उनके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए।

इस संबंध में चौकी प्रभारी महावीर वर्मा ने बताया कि, लक्ष्मण के पिता भुंडा ने ही चौकी में आवेदन दिया था। जिस पर पुलिस गई थी। कीटनाशक पीने के बाद पुलिस ही लक्ष्मण को खवासा लेकर आई। यह सही है। यह भी सही है कि, लक्ष्मण के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं हुई थी, पर जांच हेतु लेने गए थे।

आत्मनिर्भर भारत में होगा मप्र का महत्वपूर्ण योगदानः चौहान

भोपाल, एजेंसी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मध्यप्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और उद्योग के क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्यों के माध्यम से सशक्त अर्थव्यवस्था के लिये अधिकतम प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ वित्त मंत्री भारत सरकार के वक्तव्य के बिन्दुओं पर मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के पश्चात चर्चा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में कोरोना संकट के फलस्वरूप लॉकडाउन की लगभग दो माह की अवधि में 4600 करोड़ रूपये की राशि किसानों के खाते में जमा कर उन्हें राहत प्रदान की जा चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान?निधि योजना की राशि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास, बैटरी चलित वाहनों के उपयोग में मध्यप्रदेश लीड करने का प्रयास करेगा। इसी तरह पशुपालन के तहत गौवंश की रक्षा के साथ पशु नस्ल सुधार का कार्य अभियान के रूप में संचालित होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उद्यानिकी में कार्य की काफी संभावना हैं। प्रदेश में मधुमक्खी पालन जैसे लाभकारी कार्य से लोगों को जोड़ने के प्रयास बढ़ाए जायेंगे। विशेष रूप से मुरैना और भिण्ड जिलों में इस कार्य का विस्तार किया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने अंतर्विभागीय समन्वय से तालाब निर्माण और मत्स्य पालन के कार्यों को जोड़कर किसान के हित में योजना लागू करने के निर्देश दिये।

अर्थव्यवस्था में और नकदी की है जरूरतः गडकरी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थवस्था को गति देने के लिए बाजार में और नकदी डालने की जरूरत है और राज्य सरकारों को 20 लाख करोड़ रुपये मुहैया कराने चाहिए जबकि और 10 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक-निजी साझेदारी के निवेश से आ सकते हैं। सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं सूक्ष्म-मध्यम-लघु उद्योग एमएसएमई मंत्री ने कहा कि इससे केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज सहित 50 लाख करोड़ रुपये की तरलता बाजार में आएगी जिससे अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की वजह पड़े विपरीत असर का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा मौजूदा परिस्थितियां बहुत गंभीर है पूरी दुनिया मुश्किल का सामना कर रही है।श् मंत्री ने रेखांकित किया कि संकट से मुकाबले के लिए अमेरिका ने दो ट्रिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है जबकि जापान ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 12 प्रतिशत के बराबर पैकेज की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है। गडकरी ने कहा, श्कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब और अधिक संसाधन जुटाये जा सकते हैं और राज्य और 20 लाख करोड़ रुपये का बजट मुहैया करा सकते हैं और न्यूनतम 10 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक निजी निवेश से आ सकते हैं।

मुख्य मामले के साथ आज सुनवाई होगी

प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुरजेवाला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवासी मजदूरों की बदहाली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतरू संज्ञान लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोर्ट पहुंचे। सुरजेवाला ने इस मामले में दलीलें रखने की अनुमति मांगी। उनकी अर्जी पर भी मुख्य मामले के साथ 28 मई को सुनवाई होगी।

सुरजेवाला की ओर से वकील सुनील फर्नांडीस ने कहा कि सरकार को हर जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए हाल ही में जिन पैकेज की घोषणा की गई है, उनमें उन्हें क्या मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को लॉकडाउन के बाद देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले पर स्वतरू संज्ञान लिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था।

कोर्ट ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में प्रवासी मजदूर की दयनीय स्थिति का खबरें आ रही हैं। मजदूर पैदल और साईकिलों से लंबी दूरी तय कर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। ये मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें रास्ते में कहीं भी प्रशासन की ओर से न तो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और न ही पानी।

कोर्ट ने कहा था कि संकट की इस घड़ी में समाज के इस हिस्से को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से खास मदद की दरकार है। सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में कई पत्र लिखे गए हैं, जिसमें इन मजदूरों की स्थिति को रेखांकित किया गया है। आज भी ये मजदूर रोड पर, हाईवे पर, रेलवे स्टेशनों और राज्यों की सीमाओं पर फंसे पड़े हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उनके खाने-पीने और परिवहन की व्यवस्था तुरंत करें।

कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं लेकिन वे नाकाफी हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीकृत प्रयास की जरुरत है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट की मदद करने का निर्देश दिया था और कहा कि वे 28 मई को केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

दुनिया में अध्याय बदला कोरोना के बाद बदलेगी पूरी किताबः राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस को एक जगह नहीं रोक सकते, ऐसे में केंद्र से राज्य को ताकत देनी चाहिए ताकि जमीन पर लड़ाई हो सके। वायरस की वजह से आर्थिक, स्वास्थ्य और दुनिया के सिस्टम पर सीधा असर पड़ा है। लोग कहते हैं 9/11 नया अध्याय था, लेकिन कोरोना के बाद की दुनिया नई किताब होगी।राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हुए प्रोफेसर झा ने भी कहा कि कोरोना वायरस के बाद ग्लोबल ऑर्डर बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि आज यूरोप के बड़े देश, अमेरिका किस हालात में आ गए हैं।

बता दें कि राहुल गांधी कोरोना संकट काल के बीच लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। पिछली दो बातों में राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी, इस बार हेल्थ एक्सपर्ट से बात की है।इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने प्रोफेसर से वैक्सीन के बारे में पूछा, राहुल ने कहा कि भारत को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी और दुनिया में ये कबतक आएगी। जिसपर प्रोफेसर झा ने कहा कि 3 देशों में उम्मीद है कि जल्द आएगी, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद है कि अगले साल तक वैक्सीन आ पाएगी। भारत को इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत को 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनानी है।गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से दुनिया के करीब 190 देश संकट में हैं, कुछ देशों में हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई जगह पिछले करीब तीन महीने से सबकुछ बंद पड़ा है और अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है।

सियासी लाभ के लिए गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बना रहे हैं राहुलः रविशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सियासी लाभ के लिए गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से कोरोना की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तभी से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

रविशंकर ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर नकारात्मकता फैलाने, संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम करने, झूठा श्रेय लेने, कथनी करनी में अंतर और गलत तथ्यों व झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहाकि राहुल गांधी इन पांच तरीकों से देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमला जारी रखते हुए कहा कि राहुल गांधी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों के टिकट के लिए भी झूठे आरोप लगाए कि टिकट का पैसा लिया जा रहा है। जबकि सरकार ने बार-बार बताया कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जा रहा है, टिकट के किराए में रेल मंत्रालय 85 प्रतिशत और राज्य सरकारें 15 प्रतिशत वहन कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्राहुल गांधी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्ज (आईसीएमआर) पर भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इसके द्वारा खरीददारी में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के आरोपों के कारण पहली बार आईसीएमआर को सफाई देनी पड़ी कि उसने ऐसी कोई खरीददारी नहीं की है और न्यूनतम दामों में खरीददारी की। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक विरोध में ऐसी संस्थाओं पर भी झूठे आरोप लगाने लगे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के 15 ऐसे देश जहां कोरोना बड़ी बीमारी बन गया है उसकी आबादी है 142 करोड़। उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा व अन्य देश हैं। इन देशों में 26 मई तक करीब 3.43 लाख लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है।जबकि भारत की आबादी है 137 करोड़ और हमारे देश में 4,345 लोगों की मृत्यु हुई है। 64 हजार से ज्यादा रिकवरी हुई है। वैसे मृत्यु कहीं भी हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्णबंदी (लॉकडाउन) करके देश को एकजुट किया है, यह उसी का नतीजा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार है। ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। देश को एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है।

भाजपा नेता ने कहा कि पूरा देश जब ताली बजा रहा था तो राहुल गांधी ने इसका खंडन किया। प्रधानमंत्री ने जब देश से आग्रह किया था कि कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली बजाकर, घंटी बजाकर उनका हौसला बढ़ाएं तो देश ने ऐसा किया।

सीबीएसईः 10वीं और 12 वीं की शेष परीक्षाएं अपने गृह जिले में ही दे सकेंगे विद्यार्थी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने लॉकडाउन के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने गृह जिले में ही परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। ऐसे में छात्रों को अपने स्कूल के परीक्षा केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीएसई इस संबंध में जून के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करेगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 संकट के कारण हजारों बच्चे अपने गृह प्रदेश में चले गए थे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने फैसला लिया है कि ऐसे विद्यार्थी अपनी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने गृह राज्यों में जा चुके हैं तो ऐसे में जुलाई में शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए उन्हें वापस जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे छात्रों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे उम्मीदवार अपने स्कूलों के संपर्क में रहें और सीबीएसई की अधिसूचना जारी होते ही सुझाई गई कार्रवाई करने पर अमल करें।

सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं की परीक्षा केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों को ही देनी होगी। 10वीं के कुल 6 विषयों (उत्तर पूर्वी दिल्ली) और 12वीं कक्षा के 11 विषयों की (उत्तर पूर्वी दिल्ली) और 12वीं के छात्रों को (ऑल इंडिया) कुल 29 प्रमुख विषयों की परीक्षा होगी।बोर्ड ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश का कड़ाई से पालन करने और परीक्षा केंद्रों की संख्या 15 हजार कर दी है। पहले परीक्षा केंद्रों की संख्या मात्र तीन हजार थी।

कोरोना से मुक्ति के लिए 53 दिनों से लगातार मंत्र जाप

माही की गूंज, थांदला। छोटे काशी के नाम से विख्यात धर्मनगरी थांदला में 24 घंटे सातों दिन 12 माह धर्म सत्संग कर्मकांड प्रवाहना होती रहती है। उसी कड़ी में स्थानीय सरस्वती नंदन स्वामी गुरुद्वारा भजन आश्रम के प्रभारी पंडित भूदेव आचार्य के द्वारा वर्तमान में संपूर्ण विश्व के सामने चुनौती बनकर आई कोरोना महाव्याधि के भय से मुक्ति हेतु पिछले 53 दिनों से लोक प्रयोजनार्थ प्रतिदिन अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12रू20 बजे से सूर्य नारायण भगवान के सम्मुख मंत्र जाप साधना की जा रही है। जिनके मार्गदर्शन में अन्य शिष्यों के द्वारा भी मंत्र जाप साधना की जा रही है।

आचार्य ने बताया कि सूर्यदेव सदैव तेज, शौर्य, साहस के वाहक रहे हैं। जिनकी साधना से बड़े-बड़े प्राकृतिक संकट से आम जनों को मुक्ति मिली है। वेदों में उल्लेखित मंत्र ़ष्? घृणिरूसूर्य आदित्योम्ष् के अनुसार भगवान सूर्य देव की साधना सर्वजन हितकारी और फलदायी रहती है। उसी कड़ी में प्रतिदिन इस मंत्र का जाप किया जा रहा है। निश्चित तौर पर नगर सहित संपूर्ण विश्व इस महामारी से जल्द ही मुक्त होगा क्योंकि मंत्र साधना सर्वजन हितकारी होती है। जिसका उद्देश्य लोकहित होता है।

न्यास के ओम शर्मा के सुझाव पर मांशिम ने दी विद्यार्थियों को सुविधा

माही की गूंज, झाबुआ। वर्तमान में विश्व कोविड-19 की महामारी से जुझ रहा है। संपूर्ण भारत में इसके कारण 24 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति है। माशिम की मार्च माह में आयोजित परीक्षाओं को इसी कारण तब स्थगित कर दिया गया था, जिन्हे अब आगामी 9 जून से की जाने की योजना हैं। इन परीक्षाओं के संबंध में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्र सह संयोजक ओम शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया था कि लॉकडाउन के कारण विस्थापित हुए बच्चों की शिक्षा की निरंतरता के लिए विशेष प्रयास किए जाना चाहिए। इस आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही करते हुए माशिम को तत्संबंधित आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिसके परिपालन में माशिम ने ऐसे समस्त छात्रों को अपने वर्तमान में निवास के जिले से हीर परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिये प्रक्रिया जारी कर दी हैं। ओम शर्मा ने इस त्वरित कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए व्यापक छात्रहित में इस प्रक्रिया के पंजीयन की समयावधि में वृद्धि के साथ परीक्षा आयोजन की भी तिथियों में परिवर्तन कर आगामी जुलाई माह में आयोजन करने का सुझाव दिया है।

लॉक डाउन के चलते सम्पत्ति कर माफ करने की मांग की गई

माही की गूंज, झाबुआ। कोरोना वायरस की महामारी से पूरा देश झूझ रहा है। प्रधानमंत्री के आव्हान पर पूरे देश में 25 मार्च से लॉक डाउन सतत चल रहा है । जिसके चलते आम लोगों की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है तथा जनता भी इसको लेकर परेशान नजर आ रही है। शासन के निर्देश के अनुसार नगर पालिका एवं जिले की नगरीय निकायों द्वारा संम्पत्ति कर एवं जल कर की राशि का भुगतान किया जाना है। चूंकि लॉक डाउन के चलते करीब करीब हर परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे में नगर पालिका के मुख्य नपा अधिकारी एलएस डोडिया से तथा नपा अध्यक्ष श्रीमती मन्नू डोडियार के अलावा जिला प्रशासन एवं राज्य शासन से मांग की गई है कि नगर में संम्पत्ति कर को आगामी तीन माह के लिये समय देकर अभिवृद्धि की जाये। वही सामान्य एवं गरीब परिवारो के लोगो के मकान आदि के सम्पत्ति कर को माफकरने की मांग भी उठाई जा रही है। नगर पालिका, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार जनहित में निर्णण लेकर लोगो को राहत दिलाने का काम करेंगे।

सांसद जी एक साल, 202 परिवार बेहाल

प्रधानमंत्री आवास की फाइल एक साल से लगा रही ऑफिसों के चक्कर

भाजपा समर्थित पेटलावद के 202 हितग्राहियों पर छत का संकट नहीं देख पाए सांसद डामोर

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

लगातार विवादों में घिरे रतलाम झाबुआ-अलीराजपुर लोकसभा सीट से सांसद गुमानसिंह डामोर फिलहाल अपने सांसद के रूप में एक वर्ष पूर्ण करने का जश्न मनाने में व्यस्त हैं। कुछ एक अखबारों के पन्ने और सांसद समर्थकों ने सांसद के एक सफलतम वर्ष की बधाइयों से रंगे जा रहे हैं, लेकिन पेटलावद की जनता सांसद महोदय के एक साल के कार्यकाल से इत्तफाक नहीं रखती और न ही सांसद डामोर के इस एक साल को सफल मानती हैं। जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण खुद सांसद डामोर हैं, जो अपने इस सफल वर्ष में पेटलावद की उस जनता को कोई बड़ी सौगात नहीं दे पाए। जहां से सांसद पांच हजार से अधिक की लीड लेकर लोकसभा में विजय हुए थे। जिले के कई बड़े शहरों को देखा जाए, तो पेटलावद अपनी भाजपाई मानसिकता के चलते हमेशा भाजपा के लिए बड़ी जीत यहां से दर्ज करते आए हैं, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार और यहां भाजपाई सांसद के विजय होने के बाद भी पेटलावद नगर के लोग किसी बड़ी योजना के लिए मुंह धोकर बैठे हैं, जो केंद्र से सांसद के प्रयासों से आई हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा हैं क्योंकि वर्तमान में किसी बड़ी योजना पर कोई काम पिछले एक साल में नहीं किया गया हैं।

केंद्रीय योजना की फाइल जिले में खा रही धक्के, 202 लोग आवास के इंतजार में

भाजपा राज्य सरकार में अभी-अभी आई ही है। केंद्र में मोदी सरकार अपना एक वर्ष पूर्ण कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबसे महत्त्वकांक्षी योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके द्वारा 2024 तक हर परिवार को पक्का बना कर देने की योजना है। इसी योजना के पेटलावद के 202 हितग्राहियों के नाम शामिल हैं। जिसकी समस्त आवश्यक कार्यवाही नगर परिषद पेटलावद द्वारा की जा चुकी है। योजना के लाभ के लिए पहली किस्त के लिए केंद्र से दो करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत होकर नगर परिषद के खाते में जमा हुए लगभग 08 माह से अधिक का समय हो गया हैं, लेकिन अब तक योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल सका हैं। जिसका मुख्य कारण योजना की फाइल लगातार पेटलावद से झाबुआ और झाबुआ से पेटलावद के ऑफिस में घूम रही है। ऐसा भी नहीं कि मामले की जानकारी नहीं होगी।

आवास का फाइल फोटो

माही की गूंज सहित कई समाचार पत्र मामले को प्रमुखता से उठा चुके हैं, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार के नुमाइंदे होकर भी सांसद इस योजना का लाभ अब तक हितग्राहियों को नहीं दिला सके है। आज भी योजनाओं की फाइल अंतिम चरण में होना बता कर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजी जा रही है।

मकान की आस में छत का संकट, हो चुकी हैं कई शिकायतें

वर्ष 2014 में हुए नगर परिषद सर्वे और नगर परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार समस्त दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण कर 202 लोगों को चयनित कर प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत होने के लिए भेजा गया, जिसमें स्वीकृति के बाद राशि तक आंवटित हो गई। नगर परिषद और उनके पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के हितग्राहियों को मकान स्वीकृति होने और राशि आने की बात बोली गई, तो ज्यादातर हितग्राहियों ने मकान बनाने की चाह में दूसरे मकान किराये लेकर मकान खाली कर दिए। लेकिन लगातार 08 माह से भी अधिक समय निकल जाने के बाद भी राशि नहीं मिलने पर दूसरे मकान का अतिरिक्त किराया वहन करना पड़ रहा है। कुछ हितग्राहियों ने तो मकान खोल भी दिए, लेकिन राशि नहीं आने से कार्य अटक गए। जिससे रहने का संकट खड़ा हो गया। मकान की आस में और देरी से परेशान हितग्राहियों ने 181, जनसुनवाई और पिछली सरकार द्वारा वार्ड में किए गए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लिखित आवेदन दिए, लेकिन शिकायतों के निराकरण में कोई जवाब नहीं आया।

शेष पृष्ठ 7 पर देखें...

जिला फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर एसोशिएसन ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर एसोसिएसन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन सौंपा गया। कोविड-19 महामारी को लेकर जहां पूरे देश में लाक डाउन चल रहा है ऐसे में फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर का धंधा बंद पड़ा हुआ है । बैंक का लोन एवं दुकान का किराया किस प्रकार चुकाए इसकी परेशानी दिन रात सताये जा रही है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री से झाबुआ जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन ने मांग की है, ऐसी योजना बनाएं जिससे फोटोग्राफरों एवं विडयोग्राफरों को राहत मिले एवं उनके जीवन व्यापन करने मे सहुलियत मिल सके।

पेटलावद में भी दिया ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद। जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन झाबुआ के नेतृत्व में सोमवार को एसडीएम एमएल मालवीय को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। जिसमें बताता की वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश में टोटल लॉकडाउन की वजह से आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में फोटोग्राफी, वीडियो ग्राफी व्यवसाय से जुड़े स्टूडियो, आउटडोर, फोटोग्राफर, वीडियो ग्राफर व अन्य सहयोगियों के सारे मांगलिक एवं अन्य कार्यक्रमों की बुकिंग निरस्त हो चुकी है। कई फोटो व वीडियो ग्राफर के अपने व परिवार के पालन पोषण के लिए इस व्यवसाय के अलावा अन्य कोई साधन नही है। वही लॉक डाउन के चलते उनकी आये के साधन बन्द हो गए है, ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। फोटोग्राफर व वीडियो ग्राफर ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए मांग की है कि फोटोग्राफी व्यवसाय के भविष्य के लिए भी कोई मजबूत योजना बनाकर सहयोग किया जाए जिससे कि ऐसे समय मे उन्हें किसी परेशानी से नही गुजरना पड़े। फोटोग्राफर मोहन पडियार ने बताया कि हमारे पास फोटोग्राफी के अलावा कोई अन्य कार्य नही है। तथा कार्यक्रमों में वीडियो व फोटोग्राफी का काम पूरा होने के बाद ही हमे रुपया मिलता है। वर्तमान में हमारे पास कोई काम नही है, ऐसे में सरकार को हमारे बारे में सोचकर आर्थिक मदद के साथ ही भविष्य के लिए एक मजबूत योजना बनाई जाए ताकि हमे किसी संकट का सामना नहीं करना पड़े। ज्ञापन देते समय पेटलावद नगर के समस्त फोटोग्राफर उपस्थित थे। इस दौरान शोसल डिस्टेसिंग का पूरा पालन किया गया।

21 दिनों में 274 सैंपल ने हर पल डराया, मिले 13 पॉजिटिव

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले 21 दिनों के तनाव भरे पलों से उबरकर अब आगे की राह देखी जाने लगी है। इन 21 दिनों में 274 सैंपल जिले से इंदौर की लेब में भेजे गए। इनमें भी केवल 13 पॉजिटिव मरीज मिले, लेकिन हर मरीज के सामने आने के बाद अफवाहें लगातार दहशत फैलाती रही। अब जाकर कोरोना अध्याय थमा है, लेकिन तीन दिनों के बाद मंगलवार को बैंक खुली तो फिर से यहां उमड़ रही ग्रामीणों की भीड़ डराने लगी है। कोरोना वायरस संक्रमण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। झाबुआ जिले में यह महामारी लंबे समय तक अपने पैर नहीं पसार पाई। मार्च व अप्रैल में वायरस पड़ोसी जिलों में होने के बावजूद यहां प्रवेश नहीं कर पाया। आखिरकार 6 मई को पहला कोरोना का मामला सामने आया।

तनाव बढ़ता चला गया

संक्रमण के जिले में दस्तक देते ही 274 सैंपल बारी-बारी से इंदौर भेजे जाते रहे। जैसे-जैसे पॉजिटिव मरीज बढ़ते गए, सैंपल को लेकर तनाव बढ़ता चला गया। जिस जिले में एक भी केस नही था, वहीं 13 पॉजिटिव मरीज सामने आ गये। नाहरपुरा के अलावा सभी मामले जिला मुख्यालय से आए। हुडा व गोपाल कॉलोनी की एक गली में ही संक्रमण ने पैर पसारे। दोनों को ही सील किया गया, लेकिन केस आना नहीं रुके।

फिर भीड़ हो गई

तीन दिनों के अवकाश के बाद मंगलवार से बैंक खुले। सभी बैंकों के बाहर भीड़ जमा होरही है । शारीरिक दूरी मापदंड की भी धज्जियां उड़ने लगी। साथ ही यह संकेत भी मिलने लगे कि कहीं फिर से कोरोना का कहर शुरू नही हो जाये। फिलहाल अध्याय इसलिए थमा, क्योंकि झाबुआ शहर में पॉजिटिव मरीजों के सम्पर्क में आने वालों के सैंपल नेगेटिव आ चुके है। 6 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके है। अन्य 4 पॉजिटिव मरीजों को भी घर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद केवल 2 एक्टिव केस बचेंगे, लेकिन सामान्य स्थिति में वे है तो सारा मामला औपचारिक ही रह गया है। अब जरूरत सिर्फसावधानी बरतने की है।

तपती धूप में खड़े रहते हैं घंटों

ग्रामीण सुबह से ही पैसा निकालने के लिए बैंकों के बाहर एकत्रित हो जाते है। तपती धूप में दिनभर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते है। यहां पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पाता है। महिलाओं व पुरुषों की अलग-अलग लाइन लगती है। बैंकों के बाहर कोई भी धूप से बचने का इंतजाम नहीं रहता। एक-एक ग्रामीण को 3-4 घंटे धूप में इंतजार करने के बाद उनका नंबर आ पाता है जबकि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लोगों ने मांग की थी कि ग्रामीणों को उनका पैसा कियोस्क सेंटर के माध्यम से गांव में ही वितरित कर दिया जाए तो बैंकों के बाहर भीड़ न लगे।

मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस बारिया ने बताया कि कोरोना की चौन शहर में चल पड़ी थी। इसलिए लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे। अब यह चेन टूट गई है।

लॉकडाउन अवधि का छात्रों का किराया सरकार वहन करें- कांतिलाल भूरिया

माही की गूंज, झाबुआ। वर्तमान में कोराना महामारी के चलते देश सहित प्रदेश के सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय बन्द है, जिसमें छात्र जो अध्ययन कर रहे थे वे अपने अपने गृह निवास प्रस्थान कर गए है। किन्तु वे जहां अध्ययनरत थे वहां के मकान एवं निजी छात्रावास अथवा कमरों का किराया निरन्तर चालू है उसे सरकार को वहन करना चाहिए। उक्त बात झाबुआ विधायक कांतिलाला भूरिया तथा विधायक प्रतिनिधि डॉ. विक्रान्त भूरिया ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि वर्तमान में लॉकडाउन के चलते प्रदेश के बड़े शहरों में निवास कर रहे है छात्र अपने अपने घर लौट गये है किन्तु उनके मकान एवं निजी छात्रावास जहां वे रह कर अध्ययनरत थे वहां का किराया शासन को देना चाहिए। उक्त मांग विधायक कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से पत्र लिख कर की है।

एसडीएम खराड़ी की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए व्यापारियों ने किया अभिनंदन

माही की गूंज, झाबुआ। अंचल में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अनुविभागिय अधिकारी डॉ अभयसिंह खराडी को नगर के नागरिको ने हार-फुल एवं शाल-श्रीफल से भावभरा स्वागत किया गया।

वही उनके द्वारा झाबुआ अनुविभाग के साथ ही नगर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाकर अपनी सेवा भावना का परिचय कर कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने का हरसंभव प्रयास किया। डॉ खराड़ी वैसे तो मिलनसार एवं सहयोगी भावना के व्यक्तित्व माने जाते है किन्तु बावजूद इसके शासन के नियम निर्देशो के साथ ही शहर में कोविड-19 के प्रभाव को रोकने की दिशा मे उनकी सख्ती निश्चित ही काबिले तारीफ मानी जाती है। चाहे लोग उन पर भेदभाव का आरोप लगाए किन्तु जो कार्य करता है उसे आक्रोश का सामना करना पड़ता है। वे इस दिशा में सफल भी रहे है, प्रशासन स्तर पर उन्हे एक सफल प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुये झाबुआ के व्यापारियों की ओर से थांदला गेट स्थित एकलव्य भवन परिसर के आगे सार्वजनिक रूप से उनका स्वागत किया जाना एक कोरोना योद्धा के रूप में नगर के लिए गौरव का विषय है।

कोरोना का असर, हनुमानजी ताले में, रोजी-रोटी लाले में

विश्वमंगल तारखेड़ी पर भी कोराना का दिखाई दिया असर

माही की गूंज, झाबुआ।

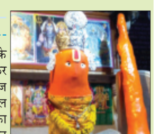

श्री विषमंगल हनुमानजी

देश मे कोरोना के संकट ने लोगो के साथ ही भगवान को भी लॉकडाउन कर दिया है। आज मंगलवार है और आज राम भक्त हनुमान श्री विश्वमंगल तारखेड़ी धाम पर हजारों लोगों का आना-जाना होता है। लेकिन लॉकडाउन का सीधा असर मंदिर- मस्जिदों पर हुआ है। आज के दिन भगवान विश्वमंगल हनुमानजी के दर्शनलाभ व उनका आशीर्वाद तो श्रद्धालुओं को मिल ही जाता है किंतु मंदिर पर आए श्रद्धालुओं से कई गरीब परिवारों की रोजी-रोटी भी चलती है। श्री विश्वमंगल तारखेड़ी धाम पर क्षेत्र सहित आस पास के जिलो एवं दूर दराज से लोग मंगलवार को अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते है। और भगवान हनुमानजी के दर्शन कर अपने आप शोभाग्यशाली मानते है। किंतु देशभर में कोरोना का संकट बना हुआ है जिससे आम लोग तो घरों में बंद है किंतु इस संकट के चलते मंदिरों पर भी ताले लगे हुए है। श्री विश्वमंगल तारखेड़ी धाम पर पुजारी द्वारा पूजा-अर्चना की जा रही है किंतु बाहर से कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नही कर पा रहा है क्योंकि कोरोना संकट की वजह सभी लोग अपने घरों ने बंद है। ऐसे ने मन्दिर पर भी कोई नही पहुच पा रहा है।

मंगलवार सहित आम दिनों में श्री विश्वमंगल तारखेड़ी धाम पर हजारो लोग पहुंचते है जिससे वहां पर फूल-अगरबत्ती बेचने वाले गरीब परिवारों के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था हो जाती है, किन्तु कोरोना संकट के चलते मंदिर पर श्रद्धालु नही पहुंच रहे है जिससे इन गरीब परिवारों पर भी रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा। इसी लिए हमने हमारी खबर का शीर्षक दिया है 'कोरोना का असर, हनुमानजी ताले में, रोजी रोटी लाले में।'

जब विश्वमंगल धाम तारखेड़ी मंदिर के बारे में मितली जानकारी के अनुसार मंदिर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ गरीब लोग कुछ पैसों की आस में अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठे है किन्तु वहां उनके फूल- अगरबत्ती खरीदने वाला कोई नही है। कोरोना का सीधा असर गरीबो की रोजी रोटी पर भी हुआ है। ऐसे में जिन परिवारों की रोजी-रोटी मंदिर पर फूल-अगरबत्ती बेच कर चलती थी उ के सामने एक बड़ा संकट खड़ा है। क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में कब लॉकडाउन खुलेगा ओर कब इन गरीब परिवारो मुसबीत दूर होगी।

डाटा ऑपरेटर की गलती का परिणाम भुगतने को मजबूर किसान

गलत नंबर पर गए मैसेज के कारण समय पर मंडी नहीं पहुंच सकी फसल

माही की गूंज, पेटलावद।

15 अप्रैल से सोसायटियों और मंडी के माध्यम से शुरू हुई किसानों की गेहूं की फसल की खरीदी के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। इस बार गेहूं की बम्पर आवक के कारण मंडी और सोसायटियों के बाहर किसानों और गेहूं से भरे वाहनों की लंबी कतारें आम हो गई है। शुरू-शुरू में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस के चलते 5 से 10 किसानों को ही मंडी तक बुलाया गया, लेकिन किसानों के अधिक पंजीयन को देखते हुए लॉकडाउन छोड़कर एक साथ कई किसानों के एक दिन गेहूं की तुलाई हेतु पहुंचने के मैसेज पहुंच गए। जिससे किसानों के साथ-साथ गेहूं खरीदे में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी परेशान होना पड़ा। इधर, लाइन में लगे किसान परेशान थे तो दूसरी ओर ऐसे भी किसान थे, जिनका पंजीयन तो था, लेकिन उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा। अंतिम तिथि पास आते देख किसान अपनी उपज लेकर सोसायटी पहुंच गए, तो वहां पता लगा कि पंजीयन में जो नम्बर थे वो गलत डाल दिए। इस वजह से मैसेज दूसरी जगह पहुंच गया। तो कई किसान ऐसे भी थे, जिनकी आधी फसल ही एक दिन में तोली गई और बाकी की फसल के लिए जो तारीख दी गई उस पर गेहूं नहीं तोले जा सके।

पेटलावद के किसान रामचंद्र सिर्वी जब पेटलावद सोसाइटी में अपनी उपज लेकर पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि आपका मोबाइल नम्बर गलत इंट्री होने की वजह से मैसेज दूसरी जगह चला गया हैं। आपकी गेहूं तोलने की तारीख 20 मई थी जो कि निकल चुकी हैं। किसान रामचंद्र सिर्वी ने बताया कि मेरे द्वारा सही नम्बर दिया गया था डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा की गई गलती का परिणाम मेरे जैसे कई किसान भुगत रहे हैं। मंगलवार को जब गेहूं लेकर पहुंचा तो वहां मौजूद अधिकारियों बोला कि मैसेज की दिनांक से 48 घंटे में बिलिंग करनी होती हैं। ऐसा नहीं होने पर गेहूं नहीं तोल सकते। अब नए मैसेज का इंतजार करना पड़ेगा। उधर, कई किसानों की फसल को हल्की, छोटे गेहूं और कचरा अधिक होने की बात कर कम भाव में बिलिंग की जा रही है या फिर उनके गेहूं खरीदने से मना किया जा रहा है।

रूपगढ़ के किसान कांतिलाल काग ने बताया कि तुलाई में लगे कर्मचारियों के जिन किसानों से अच्छे संबंध हैं या किसानों की आड़ में व्यापारियों द्वारा कैसा भी गेहूं लाया जा रहा है वो बिना देखे खरीदा जा रहा है, जबकि छोटे किसानों की फसल में मिनमेक निकाल कर कम भाव में बिलिंग की जा रही हैं या फिर गेहूं तुलाई से मना किया जा रहा है। मामले में आदिम जाति सेवा संस्था के प्रबंधक ओझा से चर्चा करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं हो सकी।

खरीदी की तारीख और आगे बढ़ाने की मांग

किसानों की भीड़ और बाकी रही तुलाई के कार्य को देख कर राज्य सरकार ने अंतिम तिथि को 26 मई से बड़ा कर 31 मई कर दिया है, लेकिन किसानों ने इसे और आगे बढ़ाने की मांग की है। भाजपा के युवा नेता प्रदीप काग ने बताया कि सोसाइटियों में आगे लगी भीड़ और बाकी रहे पंजीकृत किसानों को देखते हुए गेहूं खरीदी की तिथि और 7 दिन बढ़ाने की मांग प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से की जाएगी।

शासकीय योजनाओं के लाभ के इंतजार में बुजुर्ग और विकलांग दंपति

सरपंच-सचिव को नहीं है योजनाओं का लाभ दिलाने में रुचि

माही की गूंज, पेटलावद। समीपस्थ ग्राम पंचायत असालिया में लगातार सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। या यूं कहें कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को केवल उन्हीं कामों में रुचि है, जहां सीधा पैसा पंचायत के खाते से आहरण किया जा सके। शासन की महत्ती योजनाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान देने का प्रावधान कर रखा है। जिसमें ग्राम पंचायत एजेंसी बनी हुई है, जो जमीन पर ऐसे लोगों को लाभ दिलाकर शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुचाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा।

ग्राम पंचायत असालिया के मनिया गरवाल की स्थिति बेहत ही गंभीर होकर वर्षो से पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान में रहने पर मजबूर है। कई बार ग्राम पंचायत के चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मनिया और मनिया की पत्नी काफी बुजुर्ग होने के बाद भी वृद्धा पेंशन तक का लाभ नहीं दिया गया। मनिया की पत्नी तो शारीरिक रूप से विकलांग होकर न तो सुन सकती हैं न ही बोल सकती हैं। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति शासन से मिलने वाली योजनाओं की राह देख रहा है, जबकि ग्राम पंचायतों को साफ निर्देश हैं कि शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएं।

मनिया गरवाल ने बताया कि जब भी ग्राम पंचायत में जाते हैं, उन्हें जब काम होगा तब बता देंगे, बोलकर भाग दिया जाता है जबकि ग्राम पंचायत में ऐसे कई मामले है जिनको योजना के लाभ के दायरे नहीं आने के बाद भी लेनदेन कर लाभ दिया गया। आखिर वो पंचायती राज भी किस काम का, जिससे ऐसे लोगों तक योजना नहीं पहुंच सके।

धृतराष्ट बने अधिकारी की नाक के नीचे ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर

समाचार पत्रों में हो रहे खुलासे, अंधों के शहर में आईना बेचने जैसा

माही की गूंज़, पेटलावद।

पेटलावद विकास खण्ड में अधिकारियों को ग्रामीणों के विकास और शासन की योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारियों ने धृतराष्ट्र बने कर ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार ऐसे ही देख रहे हैं जैसे महाभारत में एक-एक करके अपने सौ पुत्रों को मरते देखते रहें, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठा सके जिससे पुत्रों की मृत्यु को रोका जा सके। समाचार पत्रों में रोज विकास खंड की एक न एक पंचायत के खुले भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, लेकिन जवाबदारों के कानों पर जूं तक नही रेंग रही। ऐसा लग रहा है जैसे अंधों के शहर में आइना बेचने का कार्य हो रहा है। शासन ने अपनी योजनाओं का लाभ देने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया है। जिससे गांवों का विकास हो, पर जिस तरह से शासन को चुना लगाने का काम ग्राम पंचायतों में हुआ है।

उसका स्तर पेटलावद जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा के ग्राम ग्वालरुंडी में देखा जा सकता है। ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा के ग्राम ग्वालरुंडी में 2,59,200 रुपए की लागत का रोड़ सन् 2017 में स्वीकृत हुआ था, जिसमें आज दिनांक तक धरातल पर मिट्टी है। सीसी रोड लालू हटीला के घर से भेरू हटीला के घर तक मंजूर हुआ था। आज दिन तक रोड़ का निर्माण नहीं हुआ है। रोड़ केवल कागजों पर ही बना है। सरपंच सचिव और अधिकारियों की सांठगांठ से सारी राशि का आहरण कर गबन कर लिया गया और धरातल पर आज भी मिट्टी उड़ रही है। गवालरुंडी के लोग परेशान हो रहे हैं।

ऐसे एक नहीं कई ग्राम पंचायतों में कई मामले हैं। जहां बिना काम किए या स्टीमेट से कम किए काम के बाद भी पूरी राशि निकल कर हड़प ली। रिश्वत और पैसे के लोभ में अधिकारी इतने अंधे हो गए कि जिन बिलों का भुगतान करना है। उनकी एजेंसी तक नहीं देखते। कपड़े, दवाई, स्टेशनरी के व्यापारियों द्वारा निर्माण सामग्री के फर्जी बिल पास किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत में 2019 में स्वीकृत पृथ्वीराज के घर से राजू के घर तक का 49 हजार रुपए का रोड आज दिन तक नहीं बना और पूरा भुगतान अजयकुमार केशवलाल मेहता, सेमरोड नाम की फर्म का सीमेंट का बिल लगा कर दिया। जबकि बिल लगाने वाले सचिव से लेकर उपयंत्री, कम्प्यूटर ऑपरेटर और अधिकारियों को अच्छे से जानकारी में होगा कि रोड़ निर्माण केवल में सीमेंट के साथ दूसरा बहुत सारा मटेरियल और मजदूर भी लगते हैं। इसके बाबजूद रिश्वत की आड़ में सब ऐसे अंधे हो गए कि किसी नियम कानून को ध्यान में रखे बिना ही बिल अपलोड कर भुगतान कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव ने इसकी सारी राशि हड्प ली है। पूरी पंचायत में इस प्रकार के मामले है, जो जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मामले की शिकायत ग्वालरुंडी निवासी अमृतलाल भाबर ने जनपद सीईओ से की है। यहां भी जांच का आश्वासन पूर्व की शिकायतों की तरह दिया गया है। जांच होगी और फिर कार्यवाही भी होगी। इस पर साफसंदेह किया जा सकता हैं, क्योंकि इससे पहले भी ग्राम पंचायत असालिया, महुवड़ीपाड़ा कला, बरवेट, मोहकमपुर, खोरिया जैसी कई भ्रस्ट पंचायतों की कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं।

एक वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ता बताएंगे सरकार की उपलब्धियां- नायक

माही की गूंज़, झाबुआ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर केन्द्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे।

नायक ने बताया कि यह वर्ष अपने समाज में वैचारिक, आर्थिक और राष्ट्रीय अभियान के मानकों पर सर्वश्रेष्ठ वर्ष कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने उन सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है। जिनकी प्रतिक्षा लंबे समय से की जा रही थी। चाहे वह कश्मीर का मामला हो, राम मंदिर का विषय हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, तीन तलाक हो, कोरोना महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमताओं का लोहा सारे विश्व ने माना है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की ओर जो कदम बढ़ाया है, वह निश्चित ही देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।

केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा इस संबंध में विविध प्रकार के अभियान संचालित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम संगठन द्वारा संपन्न किये जाने है। उनके संबंध में 27 मई को प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा तथा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत द्वारा अलग-अलग समूहों से वीडियो और ऑडियो कॉफ्रेंसिंग करके विस्तृत जानकारी दी गई है। नायक ने बताया कि बताया कि 30 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ के कार्यकर्ताओं से फेसबुक पर लाइव रहकर मार्गदर्शन देंगे।

सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहे का

सीएमओ नहीं दे रहे जन समस्याओं के निवारण में ध्यान

माही की गूंज, झाबुआ।

प्रदेश में फैले कोरोना संक्रमण काल के कारण अधिकांश शासकीय कार्यालयो में कोरोना को लेकर हर संभव कार्य करवाये जा रहे है। वही दूसरी ओर शासकीय कार्यालयो में अन्य कामो की ओर कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपने मुंह फैर रखे है। जिस पर से नगर की आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है।

बात अगर कहे तो नगर पालिका विभाग जिसका नगर की जनता से सीधा सीधा संबंध होता है। जिस पर से लोगों को इस विभाग के द्वारा कई जरूरी कागजी कार्यवाही से जुड़े कई कार्यो की जरूरत पड़ती है। लेकिन वर्तमान में देखने को यह मिल रहा है कि नगर पालिका कार्यालय में सिर्फ कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर ही कार्य किये जा रहे है। वहीं दूसरी तरफ अन्य कार्यों पर जैसे प्रतिबंध सा लग चुका है। जिसके कारण नगर की आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। नगर पालिका विभाग में ना ही नवीन कूपन, ना ही विधवा पेंशन योजन, इन्द्रा आवास योजना, मुख्यमंत्री श्रम पंजीयन योजना आदि कई केन्द्र तथा राज्य की योजनाओं के कार्यों की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। ऐसे मे नगर की ही एक महिला वार्ड क्रमांक 13 की रमता भूरिया जो कि नवीन कूपन बनाने के लिए करीब नगर पालिका कार्यालय में 7 से 8 बार आ चुकी है। जिस पर से इस महिला को नगर पालिका कर्मचारियो के द्वारा यह कहकर उल्टे पैर लौटा दिया जाता है कि अभी वर्तमान मे कोरोना संकट चल रहा है सभी की ड्यूटी उसी मे ही लगी हुई है। ऐसे कई आम लोग है जो अपने कार्यो के लिए पिछ्ले कई दिनो से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे है। लेकिन हर बार उन्हे सिर्फ कोरोना का डर बताकर कर्मचारी एवं अधिकारी अपने कार्यों से पल्ला झाड़ रहे है।

सही बात है कि जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। जब नगर पालिका अधिकारी ही अपने कर्वात्व्य स्थल पर बहुत कम दिखाई देते है तो अन्य कर्मचारी तो नदारद दिखेगे ही। विभाग की इस तरह की लापरवाही के चलते ना जाने नगर के कितने लोगो आये दिन परेशान हो रहे है। वही दूसरी ओर उनकी ना ही कोई सुनने वाला है ओर ना ही उन्हे सही जवाब देना वाला है। अब नगर के लोगों के सामने कोरोना का तो संकट मंडरा ही रहा है लेकिन नगर पालिका विभाग के चलते अन्य योजनाओ से भी वंछित होना पड रहा है। अब आम जनता आखिर करे तो क्या करे कहा जाय।

पं. नेहरू की 56 वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने स्मरण कर दी श्रद्वांजलि

माही की गूंज, झाबुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को गोपाल कॉलोनी स्थित विधायक कार्यालय में श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव सक्सेना, जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भटट् एवं कांग्रेस पदाधिकारी जितेन्द्र शाह सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बारी-बारी से भारत के महान निर्माता को स्मरण करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव सक्सेना ने कहा कि 21वीं सदी में भारत का जो स्वरूप आज दुनिया के सामने है वह पंडित नेहरू की ही देन है। भारत के औद्योगिकरण एवं नवनिर्माण की नींव पंडित नेहरू ने ही अपने प्रधानमंत्रीकाल में रखी थी।

जिला कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष भटट् ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। आज नेहरू देश के लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने भारत के नवनिर्माण एवं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में पंडित नेहरू के ऐतिहासिक योगदान रहा है। वे सारे राष्ट्र को एकजुट करके सबकी प्रगति के पक्षधर थे। उन्होंने भारत के संविधान की मंशा के अनुसार वंचित वर्गों को समुन्नत वर्गों की बराबरी में खड़ा करने के लिए अविस्मरणीय काम किया था। इस अवसर पर जितेन्द्र शाह ने भी अपने विचार रखे कार्यक्रम के अंत में दो मिनट का मौन रख कर श्रध्दांजली अर्पित की। इस अवसर पर राकेश राठोर, दिलीप भूरिया, आलोक भट्ट, प्रभु भाबोर आदि उपस्थित थे।

धारदार हथियार से की गई हत्या, मायके आई महिला को बेरहमी से उतारा मौत के घाट

माही की गूंज, झाबुआ। खेत में पड़ी महिला को जब लोगों ने देखा तो दंग रह गए। बड़ी ही क्रूरता से उस महिला पर वार कर उसे मार दिया गया था। जैसे किसी कुल्हाडी से गले के दोनों तरफ बार-बार वार कर घाव किये, सर पर भी वार किया। आस पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस, तुरंत ही मौके पर पहुंची।

कोतवाली झाबुआ थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुये कहा कि रातिमाली निवासी सकुबाई पति जालिया बिलवाल उम्र 45 के करीब, कल सुबह अपने ससुराल रातिमाली से अपने मायके टिचकिया ग्राम आई थी। और आज सुबह अपने मायके टिचकिया से लौट कर अपने ससुराल रातिमाली जा रही थी। वहीं महिला के मायके से ढेड़ से दो किलोमीटर दूर किसी शेतान नामक व्यक्ति के खेत में महिला का शव मिला। कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई हैं। वहीं महिला का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। बहुत जल्द ही पुलिस उन अपराधियों तक पहुंच जायेगी जिन कुकर्मियों ने महिला को बेरहमी से मार कर मौत के घाट उतारा है।

ग्राम पंचायत की लापरवाही से आठ दिनों से बंद अमरगढ़ रोड और नल-जल योजना

रहवासियों का आरोप- द्वेषपूर्ण कर रहे कार्य

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

बामनिया के लोग भीषण जलसंकट से गुजर रहे हैं। जिस पर तुर्रा यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अमरगढ़ रोड की पेयजल आपूर्ति की पाईप लाईन खोद कर छोड़ दी गई। पुरानी लाइन उखाड़ने के तुगलकी निर्णय से ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। जल आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई है। पूरा रोड़ बंद होने के कारण पानी के टैंकर तक आ जा नहीं रहे है। यहां तक कि दुपहिया वाहन भी नहीं चल रहे है। पूरे रास्ते पर खुदाई की मिट्टी बिखरी पड़ी हुई हैं। पैदल चलने वालों को भी दिक्कतें आ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन घरों के रहवासियों को हो रही हैं जिनके घर के सामने ये लाईन खोद रखी है। उन सभी घरों में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं खासी परेशान हो रही हैं। पीने के पानी भरने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के नाली में गिरने का डर हमेशा बना रहता हैं। लगता है ग्राम पंचायत बामनिया किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही हैं।

पाइप लाइन खोदने में भी पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। कई लोगों के ओटले जानबूझकर तोड़े गए। भरपूर जगह होने के बाद तथा सरपंच के इर्द-गिर्द घूमने वालो नेताओं के घर से दूर खुदाई की गई, जो कि यह दर्शाता है कि काम की आड़ में भी सरपंच द्वारा द्वेषता निकाली जा रही है।

अव्यवस्था की पर्याय बन चुकी बामनिया पंचायत की लापरवाही का आलम यह है कि पूरा रास्ता बंद होने के बाद भी किसी तरह के बायपास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मोहल्ले के लोगों द्वारा स्कूल के खेल मैदान वाले रास्ते को खुलवाकर आवागमन शुरू करवाया और उस रास्ते की नाली को भरकर मामाजी आश्रम रोड भी बायपास का विकल्प हो सकता था, लेकिन विगत तीन सालों से उस रास्ते के ड्रेनेज सिस्टम की नाली की फर्सी टूटी हुई है।

मोहल्ले के लोगों द्वारा सचिव और स्वयंभू सरपंच को इसकी शिकायत की गई, लेकिन आदिवासी बाहुल्य बस्ती होने के कारण विगत तीन वर्षो से इस मोहल्ले की घोर उपेक्षा हो रही हैं। बामनिया जैसी बड़ी पंचायत में अव्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी भी एक बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रही है। आखिर क्या कारण है कि लगातार भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की शिकायतों अखबारों में खबरे छपने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब तो यही है कि बामनिया पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार को वरिष्ठ अधिकारियों का मौन समर्थन प्राप्त है।

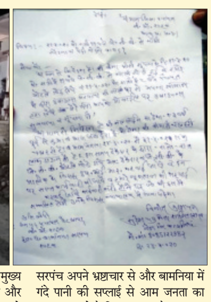

अमरगढ़ रोड रहवासी सुरेशचंद्र शांतिलाल चोरडिया का कहना है कि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत बामनिया में चल रहे भ्रष्टाचार के संदर्भ में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। इससे सरपंच नाराज है और मुझ पर जानकारी नहीं मांगने का दबाव बनाने एवं मुझको डराने के उद्देश्य से रात में जेसीबी मशीन से मेरा ओटला तोड़ा गया। मुझे बगैर सूचना दिए ये पूरी कार्रवाई द्वेषपूर्ण और बदला लेने की है। जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को की गई हैं और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा।

कांग्रेस नेता अब्दुल कय्यूम शेख का कहना है कि ग्राम पंचायत बामनिया के सरपंच द्वारा अमरगढ़ रोड पर अनावश्यक खुदाई कर पूरा रास्ता बंद कर दिया है। जिसके कारण आमजन परेशान हो रहे है। सरपंच अपने भ्रष्टाचार से और बामनिया में गंदे पानी की सप्लाई से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम कर रही हैं। मोहल्लें में द्वेषपूर्ण तरीके से लोगों के ओटले तोड़े जा रहे है। जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती हैं।

इस मामले में बामनिया ग्राम पंचायत सचिव भेरू मईड़ा से संपर्क कर जानकारी लेना चाही पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

दुर्घटना के इंतजार में बिजली विभाग

माही की गूंज़, पेटलावद।

गंभीर स्थिति में डीपी कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा।

पेटलावद के समीप ग्राम पंचायत बरवेट के पिपलीपाड़ा फलिये में बिजली विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। जिससे फलियेवासियों पर किसी बड़ी दुर्घटना का साया मंडरा रहा है। यहां पिपलीपाड़ा फलिये में लगी डीपी का एक खम्बा पूरी तरह टूट के अलग ही चुका है और कभी गिर सकता है। खम्बे के टूटने से डीपी पर से हो कर गुजर रहे तार भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गए है। बारिश का मौसम आ चुका है और रोज धूल भरी आधियां चल रही है। जिससे खंबे के गिरने और करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। डीपी के पास ही फलियेवासियों के मकान बने हुए हैं और जानवरों का भी जमावड़ा लगा रहता है।

मामले की जानकारी फलिये वालो ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। जबकि बिजली विभाग में बारिश के पूर्व मेन्टेन्स के नाम पर लाखों खर्च किए जाते हैं, लेकिन लगता हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी विद्युत तारों, खम्बों का काम और स्वयं का मेंटेनेंस अधिक करते हैं। फलिया निवासी भगीरथ अमलियार ने बताया कि जब भी ये डीपी का खम्बा गिरेगा मेरे घर या उसके आस पास ही गिरेगा। जिससे मेरे पूरे परिवार पर जान माल के नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। मामले में बिजली विभाग सारंगी के जेई से बात की तो उनका कहना है कि हमारी जानकारी में आज ही मामला आया है और जल्द ही इसे ठीक करवा देंगे।

संपादकीय

वैश्विक महामारी के बीच कुदरत का कहर

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और सुपर चक्रवाती तूफान 'अम्फान' एक साथ दो-दो कहर आपदाएं और त्रासदियां। कोई कैसे झेल सकता है? तूफान भी कुदरत का एक निश्चित चक्र है। वह चक्र समीक्षा करता है, समंदर की सफाई करता है, लेकिन असंख्य लोगों को बर्बाद और विस्थापित भी करता है। बड़े-बड़े कालजयी से प्रतीत होने वाले पेड़ भी उखड़ कर जमींदोज हो जाते हैं। करीब 500 साल पुरानी इमारत का इतिहास भी मलबा हो गया। जो संसाधन इंसान की मेधा, मेहनत और शोध क्षमताओं ने स्थापित किए थे, उनके सिरे और संचार भी गायब हो गए। मोबाइल टावर तक उड़ गया। बिजली के सैकड़ों खंभे और ट्रांसफार्मर अंततः लड़खड़ा कर जमीन पर आ गिरे और निष्प्रभावी हो गए। यह आलेख लिखने तक आधा कोलकाता और ओडिशा के आधा दर्जन इलाकों में बिजली गुल थी। नियति या प्रकृति का यह कैसा न्याय है? ये महाकहरी तूफान भी सूर्य की गर्मी और समंदर के बढ़ते तापमान से गर्म हुए पानी और फिर वाष्पीकरण और तेज चक्रवाती हवाओं की एक रासायनिक प्रक्रिया का ही नतीजा होते हैं। मौसम विभाग ने 'अम्फान' को बीते 20 सालों के दौरान सबसे विनाशकारी तूफान आंका है, लेकिन ऐसी तबाही और बर्बादी बीते 100 सालों में भी बंगाल ने नहीं देखी थी। विनाश के कुछ साक्ष्य कोलकाता, हावड़ा ब्रिज, एयरपोर्ट, उत्तर और दक्षिण 24 परगना आदि में देखे जा सकते हैं और यही कहर के शिलालेख भी हैं। बहरहाल तूफान शांत हो चुका है और बांग्लादेश के बाद खाड़ी बंगाल में समाहित हो जाएगा। लिहाजा खबर यहीं तक सिमट कर रह सकती है। ऐसा महारौद्र और तांडवी रूप महज एक खबर नहीं हो सकता। यहां से तो इतिहासों का जन्म हो सकता है। जो विनाश हुआ है, उसकी कटाई-सफाई करने के बाद सड़कें चलने लगीं या बिजली बहाल हो गई अथवा वाहन मलबा उठाने लगे, घटनाक्रम इतना ही नहीं है। हम 21वीं सदी के कालखंड में बसे हैं। दरअसल 'अम्फान' की जानलेवा गति और तांडवी उफान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जिन 6.58 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था, वे घर और लाखों लोग विस्थापित हुए थे। विस्थापन का यह दंश और त्रासदी उनके जीवन का एक तय हिस्सा बन गया है। न जाने कितनी बार वे विस्थापित हो चुके हैं और न जाने कब अगला तूफान उन्हें उजाड़ कर बिखेर देगा। 21वीं सदी में भी ऐसा इंसानी जीवन3! फिलहाल आंकड़ा यह बताया गया है कि 5500 से अधिक घर तबाह हुए हैं। अंतिम आंकड़ा मिलने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि वह अंतिम निर्णय गृह मंत्रालय के स्तर पर होता है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने एक लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नुकसान का आकलन किया है। वहां चक्रवाती तूफान 80 जिंदगियां लील गया, वैसे ममता ने पहले 72 के मरने की सूचना दी थी, लिहाजा ये आंकड़े बदलते रहेंगे। ओडिशा में भी छह जीवन नष्ट हुए हैं। तूफान ने बंगाल को ज्यादा हताहत किया है, लेकिन ऐसे जलजले तटीय इलाकों में तांडव मचाते रहे हैं। इस बार त्रासदियां इतनी घनेरी थीं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को 83 दिनों के बाद कोरोना का मोर्चा छोड़कर दिल्ली से बाहर जाना पड़ा है। वह पहले कोलकाता पहुंचे और बाद में भुवनेश्वर गए। दोनों जगह राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के साथ तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठकें भी की। जाहिर है कि आपदा और त्रासदी की इस घड़ी में आर्थिक पैकेज भी दिए जाएंगे। हालांकि आलेख लिखे जाने तक प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की थी, लेकिन यह संघीय ढांचे की औपचारिकता भर है। लेकिन जब भी आपदाकाल आता है, तो एक काटने वाला और सवालिया सच सामने आ खड़ा होता है कि देश की 73 साल की आजादी में करीब 50 करोड़ की आबादी गरीब या गरीबी-रेखा के नीचे क्यों गुजर-बसर कर रही है? आज भी करोड़ों भारतीय झुग्गी-झोंपड़ियों या कच्चे मकानों में रहने को अभिशप्त क्यों हैं? बार-बार लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर क्यों भेजा जाता है? वे हमेशा ही सुरक्षित क्यों नहीं हैं? बेशक तूफान, सुनामी आदि कुदरती चक्रों को कोई विकसित देश भी रोक नहीं पाया, लेकिन उसके समानांतर बंदोबस्त तो किए जाने चाहिए। यह यथार्थ भी एक किस्म की त्रासदी है।

राममंदिर के मिले नए पुरातत्वीय साक्ष्य और तथ्य

प्रमोद भार्गव

करीब 17 साल पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अयोध्या में राममंदिर स्थल पर किए उत्खनन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ऐसे पर्याप्त साक्ष्य और तथ्य थे, जिनसे विवादित स्थल पर राम मंदिर की सरंचना होने की पुष्टि हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में दिए इसी फैसले को मुख्य आधार बनाया था। अब रामलला परिसर में समतलीकरण का कार्य राममंदिर न्यास द्वारा कराया जा रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में तोड़े गए मंदिर के पुरावशेष मिल रहे हैं। इनमें सात काले पत्थर के स्तंभ मिले हैं। ये स्तंभ 2000 वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास व लोककथाओं के नायक विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए भव्य व विशाल राम मंदिर के इस स्थल पर होने की पुष्टि करते हैं। 84 स्तंभों वाले इसी मंदिर को 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोपों से ध्वस्त किया था। इन स्तंभों के अलावा इस समतलीकरण में रोजाना अनेक स्तंभ और देवी-देवताओं की मूर्तियां मिल रही हैं। सात फीट लंबा एक शिवलिंग भी मिला है। साफहै एएसआई के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक केके मोहम्मद ने सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी, उसमें दिए साक्ष्यों की श्रृंखला में अब रोज-रोज मंदिर के नवीन सबूत मिल रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्य के उद्घाटन के अतिरिक्त इतिहास की कोई वैचारिक अथवा सांस्कृतिक प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। इतिहास में धर्मनिरपेक्ष सोच अथवा पंथनिरपेक्ष मूल्यों का भी समावेश नहीं होना चाहिए क्योंकि तटस्थ दृष्टिकोण से लिखा इतिहास तो होता ही धर्म अथवा पंथ निरपेक्ष है। इतिहास आस्था का आधार अथवा विश्वास का प्रतीक भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आस्थाएं विवेक और तर्क का शमन करती हैं। इतिहास बौद्धिक कट्टरता का निष्ठावान अनुयायी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इतिहास से संबद्ध सांस्कृतिक संकीर्णताएं सांप्रदायिकता से कम खतरनाक नहीं है। इसलिए जब किसी प्रकरण से जुड़े नए साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हुए हों तो उनकी प्रामाणिकता सत्यापित होने पर इतिहास दृष्टि बदलना जरूरी हो जाता है। दरअसल कालांतर में इतिहास की वही लिपिबद्धता सार्थक और शाश्वत होगी जो अतीत को वर्तमान साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर यथावत प्रस्तुत करेगी। इस दृष्टि से हमारे तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवी अयोध्या विवाद से जुड़े मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उस रिपोर्ट को सर्वथा नकारते रहे हैं, जो मंदिर मुद्दे को सुलझाने में प्रमुख आधार बनी थी। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विवादित स्थल पर कराए उत्खनन रिपोर्ट को इन इतिहासकारों ने सर्वथा नकार दिया था।

मनुष्य में दो तरह की अंतर्चेतनाएं होती हैं। एक प्राकृतिक जो अवचेतन में जन्मजात संस्कारों से संचालित होती है। दूसरी का अवलंबन जिज्ञासा है, जिसकी तुष्टि हेतु ज्ञानार्जन जरूरी है। इसे अध्ययन और अनुसंधान से प्राप्त किया जा सकता है। नए साक्ष्य और प्रमाण प्रचलित मान्यता और पूर्वग्रही दुराग्रहों के परिमार्जन में सहायक हो सकते हैं। विवेकशील प्रक्रिया की यही गतिशीलता विज्ञान अथवा वैज्ञानिक समझ की द्योतक है। यही जिज्ञासा मनुष्य की आंतरिक चेतना को गतिशील व जीवंत बनाए रखने का काम करती है। इसी चेतना से प्राप्त ऊर्जा आविष्कार के नए स्रोत तलाशती है, जो पुरानी मान्यताओं पर नई मान्यता स्थापित करती है। इससे मूल्य आधारित समाज व्यवस्था समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है, तद्नुरूप समाज नए मूल्यों को धारण करता हुआ गतिशील व आधुनिक बना रहता है। लेकिन हमारे इतिहास का यह दुखद एवं शर्मनाक पहलू है कि न तो आजादी के बाद हमने भारतीय इतिहास का नए तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर पुनर्लेखन कराया और न ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का समग्र लेखन करके उसे इतिहास का हिस्सा बनाया। छोटे-मोटे प्रयास दक्षिणपंथी सरकारों ने किए भी तो उन्हें धर्मनिरपेक्ष स्वरूप खंडित हो जाने का हौवा खड़ा कर नकार दिया। इससे देश के उन सामंतों, नवाबों और जमींदारों का राष्ट्रघाती चरित्र व चेहरा जनता के सामने नहीं आ पाया जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। बल्कि कालांतर में यही राष्ट्रघाती राजनीति की अग्रिम पंक्ति में आ गए और उन्होंने लोकतंत्र में बड़ी साफगोई से सामंती मूल्यों को प्रच्छन्न रूप में पुनर्स्थापित कर दिया।

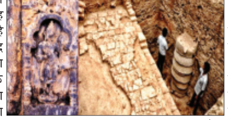

अयोध्या विवाद के सिलसिले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ के फैसले का जनता-जर्नादन ने सम्मान किया था। मुद्दे से जुड़े प्रमुख पक्षकारों ने भी मर्यादित बयान देकर संयम व विवेक की परिपक्वता दर्शाई थी। लेकिन तब संकट उन छद्म वामपंथी इतिहासकार और बुद्धिजीवियों की ज्ञान दक्षता ने खड़ा किया, जो बाबरी विवाद में मुस्लिम पक्ष को हर तरह का गोला-बारूद मुहैया कराने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। चुनौती व दिक्कत उन राजनीतिज्ञों की भी रही जो इस विवाद को भुनाते हुए अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे हैं। इसलिए आहत बुद्धिजीवी कह रहे थे कि इस फैसले में इतिहास, साक्ष्य, तार्किकता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को नजरअंदाज कर धार्मिक आस्था और दिव्यता को मान्यता दी गई है। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले का आधार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 574 पृष्ठीय प्रतिवेदन को बनाया था। दरअसल तत्कालीन एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक केके मोहम्मद ने सर्वेक्षण में पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह माना था कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मस्जिद से पहले मंदिर था। तब मस्जिद का जो कथित ढांचा था उसकी दीवारों में मंदिर के स्तंभ थे। स्तंभ के निचले भाग में 11वीं और 12वीं सदी में निर्मित मंदिरों में दिखने वाले पूर्ण कलश बने हुए थे। इसमें विष्णु हरिशिला पटल मिला था। इस पर नागरी लिपि संस्कृत भाषा में लिखा है कि यह मंदिर रावण को मारने वाले भगवान को समर्पित है। केके मोहम्मद ने कहा था कि इस खुदाई को निष्पक्ष रखने के लिए 137 श्रमिकों में से 52 मुस्लिम थे। खुदाई में जो 263 अवशेष मिले थे, उनसे यह प्रमाणित हुआ कि मस्जिद से पहले मंदिर था।

जब-जब इतिहास को किसी भी शासन या व्यक्तियों के प्रति समर्पित किया गया है, उसकी सच्चाई संदेह के दायरों में रही है। कमोबेश भारत के इतिहास का भी यही हश्र हुआ है। अफ्रीका के प्रसिद्ध कवि बोल सोयंको ने 13 नवंबर 1988 को नेहरू व्याख्यानमाला में कहा था, भारत के इतिहास ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसमें हर जगह एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। सोयंको का मानना था कि भारत का इतिहास यूरोप के हितों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दरअसल 10वीं शताब्दी में फारसी लेखक अलबेरूनी ने भारत को गलत तरीके से दुनिया में पेश करने की शुरुआत की थी। इसने लिखा था कि भारतीय लोगों में इतिहास की समझ नहीं है। इसे ही कालांतर में पाश्चात्य अंग्रेज और मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े भारतीय इतिहासकारों ने अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया। यूरोपियन इतिहासकारों ने लिखा कि भारतीय केवल धर्म और परंपराओं में डूबे रहते हैं, उन्हें बुनियादी चीजों से कोई लेना-देना नहीं है। अंग्रेज जब भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विरासत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए तो उन्होंने भारतीय इतिहास की गलत व्याख्या करनी शुरू कर दी। जिसे ढोने की परंपरा आज भी चली आ रही है।

विवादित स्थल से पुरातत्वीय उत्खनन में मिले अवशेष और अभिलेख इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की आंख खोलने वाले प्रमाण साबित होने चाहिए थे लेकिन इन्होंने उत्खनित तथ्यों को झुठलाने का हठ किया। क्योंकि ये अवधारणाएं इनकी सोच और गढ़ी हुई विचारधारा के विपरीत जा रही थीं। जबकि एएसआई द्वारा उत्सर्जित नवीन स्रोतों को शोध का नया आधार बनाकर इतिहास दृष्टि में परिवर्तन लाने की जरूरत थी। इतिहास संबद्ध इन इतिहासकारों की तार्किक विशेषज्ञता कितनी उथली और थोथी थी इसका उल्लेख उच्च न्यायालय के फैसले में माननीय न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने करते हुए लिखा था कि तथ्यों के बारे में विशेषज्ञ शुतुरमुर्ग जैसा रुख अपना रहे थे। मुकदमे में ये बुद्धिजीवी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ, इतिहासकार और पुरातत्वेत्ता के रूप में पेश हुए थे। इनके बयान कितने सतही व हास्यास्पद हैं, बतौर बानगी देखिए- सुविरा जायसवाल ने कहा था कि विवादित स्थल के बारे में उन्हें जो भी जानकारी मिली है वे समाचार पत्रों में छपी रपटों और दूसरों की बताई गई जानकारी पर आधारित है। इन्होंने मध्यकाल के इतिहास विशेषज्ञों द्वारा दी राय के आधार पर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना बयान अदालत में दर्ज कराया था। प्रकरण में गवाह के रूप में न्यायालय में पेश हुई सुप्रिया वर्मा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन को चुनौती दी थी। लेकिन उनका शर्मनाक पहलू यह रहा था कि उन्होंने एएसआई द्वारा तैयार ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार सर्वे रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी थी। खुदाई में इस आधुनिक तकनीक का उपयोग न्यायालय के आदेश से हुआ था। सुप्रिया वर्मा और जया मेनन ने एएसआई पर आरोप लगाया था कि आधार स्तंभ खुदाई स्थल पर प्रायोजित ढंग से आरोपित किए गए हैं। लेकिन अदालत ने पाया उत्खनन के दौरान वे स्थल पर मौजूद नहीं थीं। इसी तरह एक अन्य पुरातत्वविद् शिरिन भटनागर ने जिरह के बीच स्वीकारा कि उन्हें मैदान में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। कुछ इतिहास पुस्तकों की उन्होंने भूमिकाएं जरूर लिखी हैं।

न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने इन विशेषज्ञों के ज्ञान के संदर्भ में तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा, मौलिक शोध अनुसंधान और जरूरी अध्ययन किए बगैर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। इस कारण सद्भाव स्थापित होने की बजाय ये जटिलताएं, वैमनस्य और विवाद पैदा करने में सहायक बने। देश में जब-जब कोई विचारक, चिंतक, लेखक अथवा इतिहासकार, वेद उपनिषद् पुराण या अन्य प्राचीन ग्रंथ और आध्यात्मिक ज्ञान की नई देनों के साथ आधुनिक संदर्भों में व्याख्या करता है तो वामपंथियों का उसका उपहास करना एक स्थायी स्वभाव बन गया है। परंतु राममंदिर के सिलसिले में जो नित नए साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उनसे उनकी बोलती बंद है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

वैश्विक नहीं 'स्वदेशी' ही जीवन की दरकार

गिरीश्वर मिश्र

कोरोना महामारी ने जहां सबके जीवन को त्रस्त किया है, वहीं उसने जीवन के यथार्थ के ऊपर छाए कई भ्रम भी दूर किए हैं जिनको लेकर हम सभी बड़े आश्वस्त हो रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहारे हमने प्रकृति पर विजय का अभियान चलाया और उसकी उपलब्धियों के बीच यह भुला दिया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर निर्भरता और पूरकता का रिश्ता है। परिणाम यह हुआ कि हमारी जीवन पद्धति प्रकृति के अनुकूल नहीं रही और हमने प्रकृति को साधन मानकर उसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। फल यह हुआ कि जल, जमीन और जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण शुरू हुआ, उनकी जीवनदायिनी क्षमता क्षीण होती रही। साथ ही मनुष्य के अंधाधुंध हस्तक्षेप से उनके प्रदूषण का अनियंत्रित क्रम शुरू हुआ। धीरे-धीरे हाल यह हुआ कि अन्न, फल, दूध, पानी और सब्जी आदि सभी प्रकार के सामान्यतरू उपलब्ध आहार में स्थाई रूप से विष का प्रवेश पक्का होता गया। कीटनाशक रसायन और कृत्रिम खाद आदि के प्रयोग से धरती की स्वाभाविक उर्वरा शक्ति भी प्रभावित हुई। दूसरी ओर विषमुक्त या ष्आर्गनिकलीष् उत्पादित आहार (यानी प्राकृतिक या गैर मिलावटी!) जो स्वाभाविक रूप मिलना चाहिए था वह मंहगा और विलासिता का विषय होता गया। इन सबका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि आम आदमी के शरीर की जीवनी शक्ति और उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ता गया। जीवन शैली भी मनुष्य को शारीरिक श्रम से दूर करती गई। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए अवसर देने लगा। आज कैसर, हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जिस तरह बड़े पैमाने पर फैल रहा है वह इसी का प्रमाण दे रहा है।

स्वतंत्र भारत में सामाजिक स्तर पर भी देश की यात्रा विषमताओं से भरी रही। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा कि श्ग्राम स्वराजश् का विचार भुलाकर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को ही विकास की अकेली राह चुनते हुए हमने गांवों और खेती किसानी की उपेक्षा शुरू कर दी। यह भारत के स्वभाव के खिलाफ साबित हुआ और गाँव उजड़ने लगे और वहाँ से युवा वर्ग का पलायन शुरू हुआ। शिक्षा और कौशल के अभाव में इन युवाओं की शहरों में खपत ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर के रूप में हुई। बाबूगिरी की तुलना में श्रमजीवी के श्रम का मूल्य कम आंके जाने के कारण मजदूरों की जीवन-दशा दयनीय होती गई और उसका लाभ उद्योगपतियों को मिलता रहा। गरीब मजदूर मलिन बस्तियों में जीवन-यापन करने के लिए बाध्य रहे। इस असामान्यता को भी हमने विकास की अनिवार्य कीमत मान स्वीकार कर लिया। आज लाखों की संख्या में मजदूर शहर छोड़ वापस गाँव की ओर लौट रहे हैं। उन्हें वहीं जीवन की आस दिख रही है। ऐसे में कृषि और ग्राम केंद्रित व्यवस्था को सुदृढ बनाना हमारी आर्थिक नीति की वरीयता होनी चाहिए। गांवों को नगर बनाते जाना विकास की सफल युक्ति साबित नहीं हो सकी और न नगर का इतना विस्तार ही हो सका कि उसमें सबको पर्याप्त अवसर मिल सके। गांवों की परिस्थिति और व्यवस्था को हाशिये से हटाकर हमारी राष्ट्रीय सोच की मुख्यधारा में शामिल करना होगा। उनको समर्थ बनाकर ही देश का विकास हो सकेगा। इसके लिये बाजारकेंद्रित विकास की अवधारणा की सीमाओं को समझना जरूरी है। विकास में बाजार के तर्क को प्रमुखता मिलने से बाजार तंत्र के हावी होता है और उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आज महामारी के दौर में भी बाजार की सौदेबाजी चालू है और नफा का व्यापार भी।

सबकुछ बाजार की हद में लाते जाने को ही सभ्यता की निशानी मानने की प्रवृत्ति ने नगरों की व्यवस्था को भी असंतुलित किया। उनपर बढ़ती जनसंख्या के दबाव ने नागरिक सुविधाओं की अपेक्षाओं को बढ़ाया पर उतनी तैयारी और साधन के अभाव में महानगरों की स्थिति बिगड़ती गई। उदारीकरण और निजीकरण के साथ वैश्वीकरण की ओर बढ़ते कदम ने विदेशीकरण को भी बढ़ाया और विचार, फैशन तथा तकनीकी आदि के क्षेत्रों में विदेश की ओर उन्मुखता बढ़ती गई। इसी मानसिकता के अनुकूल हमारी शिक्षा प्रणाली भी पाश्चात्य बाजार प्रधान देशों के मॉडल पर ही टिकी रही। इन सबके बीच आत्म-निर्भरता, स्वावलंबन और स्वदेशी के विचारों को हम नकारते गए। उनको विकास में बाधक मानकर परे धकेल दिया गया।

करोना की महामारी ने यह महसूस करा दिया है कि वैश्विक आपदा के साथ मुकाबला करने के लिये स्थानीय तैयारी आवश्यक है। विचार, व्यवहार और मानसिकता में अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को पहचान कर उन्हें स्थापित करना पड़ेगा और आचार विचार में जगह देनी पड़ेगी। इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने श्स्थानीयश् के महत्व को रेखांकित किया है और आत्मनिर्भर बनने के लिए देश का आह्वान किया है। आशा है ग्राम स्वराज के स्वप्न को आकार देने का प्रयास नीति और उसके क्रियान्वयन में स्थान पा सकेगा। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी देश और यहाँ की संस्कृति के लिए प्रासंगिकता पर ध्यान दिया जायगा। जड़ों की उपेक्षा कर वृक्ष स्वस्थ नहीं रह सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

चाणक्य नीति

कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक ही बार होते है। इसीलिए उनका महत्व बहुत अधिक होता है। राजा लोग एक ही बार आज्ञा दे हैं और वह आदेश होता है। पंडित लोग एक ही बार बोलते हैं अर्थात् यदि किसी कार्य की पूर्ति का वचन देते हैं, तो उसका निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार माता-पिता भी अपनी कन्या का कन्यादान एक ही बार करते हैं। उक्त सभी कार्य एक ही बार किए जाते हैं। इस प्रकार आदेश, विद्वान तथा कन्याओं के विवाह संबंधी माता-पिता का वचन अटल होता है।

काम की बात

असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही दरिद्र है। सुद्गुणों से संपन्न व्यक्ति ही धनवान है।

एक सलाह

कर्म वह आईना है जो हमें अपना स्वरूप दिखाता है, इसीलिए कर्म का एहसानमंद होना चाहिए।

सुझाव अच्छे, निंदा हास्यास्पद

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

देश के 22 राजनीतिक दलों की एक संगोष्ठी में उन्होंने भारत सरकार को जो 11 सुझाव दिए हैं, उन लगभग सभी सुझावों को मैं कमोबेश अपने लेखों में पिछले दो महिने से दोहराता रहा हूं। इसीलिए उन सुझावों का तो स्वागत ही करना होगा लेकिन सरकार पर उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, वे आज के हालात में अप्रासंगिक और हास्यास्पद भी हैं। उन आरोपों और अमर्यादित कटु निंदा के कारण उनके ये रचनात्मक सुझाव भी अपना महत्व खुद घटा लेते हैं।

जैसे विरोधी नेताओं का यह सुझाव बहुत ही जरुरी और लाभकारी है कि हर परिवार को, जो आयकरदाता नहीं हैं, छह माह तक 7500 रु. प्रति मास दिया जाए। देश में आयकरदाताओं की संख्या 5-6 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 25 करोड़ परिवारों को यह राशि दी जाए। छह मास तक दी जानेवाली यह राशि इतनी बड़ी हो जाएगी कि सरकार हाथ ऊंचे कर सकती है। इस पर मेरा सुझाव यह है कि फिलहाल इस राशि को 7500 की बजाय 5000 रु. और छह माह की बजाय 3 माह के लिए कर दिया जाए लेकिन किया जरुर जाए।

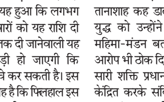

इस तरह हर जरुरतमंद को 10 किलो मासिक मुफ्त खाना देना कठिन नहीं है। सरकार के भंडारों में पर्याप्त अन्न भरा हुआ है। मनरेगा की मजदूरी 100 की बजाय 200 दिन तक देने और उसकी राशि 250 रु. तक बढ़ाने की बात मैं पहले ही कह चुका हूं। प्रवासी मजदूरों की वापसी की मांग भी उचित है और यह भी ठीक है कि 20 लाख करोड़ की राहत वास्तव में दूर के ढोल की तरह सुहावनी है।

केंद्र सरकार को चाहिए कि वे प्रादेशिक सरकारों की राय और रणनीतियों का उचित सम्मान करे, यह मांग भी ठीक है कि लेकिन अफसोस की बात है कि इतने उपयोगी सुझाव देनेवाली इस संगोष्ठी में क्षुद्र राजनीति भी अपने निर्लज रुप में प्रकट हुई। कांग्रेस की कामचलाऊ अध्यक्षा सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन्हें लगभग तानाशाह कह डाला। सारे कोरोना-युद्ध को उन्होंने एक व्यक्ति का महिमा-मंडन बता दिया और यह आरोप भी ठोक दिया कि केंद्र सरकार सारी शक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रित करके संविधान के संघवाद का उल्लंघन कर रही है। यह बात इंदिरा गांधी की बहू के मुंह से सुनने में कितनी हास्यास्पद लगती है।

कोरोना-संकट का यह समय युद्ध-काल जैसा है। ऐसे वक्त में किसी भी देश को एक सुनिश्चित और सुद्दढ़ नेतृत्व की जरुरत होती है। मोदी में जितनी भी योग्यता है, उसे वह नौकरशाहों के मार्गदर्शन में, प्रभावशाली ढंग से प्रकट कर रहे हैं। उससे ईर्ष्या करने की बजाय विरोधी दलों का रवैया रचनात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए।

छोटे उद्योगों को बाजार दो

डॉ. भरत झुनझुनवाला
आर्थिक विशलेषक

लॉकडाउन से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन छोटे उद्योगों को विशेष नुकसान हुआ है। सरकार ने छोटे उद्योगों को मदद करने के लिए तीन लाख करोड़ रुपए की विशाल राशि उन्हें दिए जाने वाले ऋण की गारंटी के रूप में देने का ऐलान किया है। इस पैकेज के अंतर्गत छोटे उद्योगों द्वारा वर्तमान में लिए गए ऋण का 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण उन्हें दिया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस ऋण के उपलब्ध होने से लॉकडाउन के समय जो उनकी हानि हुई है, विशेषकर जो उनकी तरलता समाप्त हुई है, इस अवधि को वे इस ऋण के सहारे पार कर लेंगे। लॉकडाउन समाप्त होने के साथ-साथ उनकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी और वे पुनः पटरी पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होने में संदेह है। देश के छोटे उद्योग पहले ही संकट में थे। मार्च 2019 में बैंकों द्वारा दिए गए कृषि के अतिरिक्त ऋण में छोटे उद्योगों का हिस्सा 5.58 प्रतिशत था जो फरवरी 2020 में घटकर 5.37 प्रतिशत रह गया है। यह गिरावट मामूली है, लेकिन दिखाती है कि अर्थव्यवस्था में छोटे उद्योग दबाव में हैं। बड़े उद्योगों का हिस्सा बढ़ रहा है। इस संकट को लॉकडाउन ने बढ़ा दिया है। इस परिस्थिति में छोटे उद्योगों द्वारा ऋण लेना सार्थक होगा या नहीं? उद्यमी द्वारा बनाया गया माल यदि बाजार में बिकता है, मांग होती है तो दाम ऊंचे मिलते हैं और वह प्रॉफिट कमाता है। इस परिस्थिति में वह ऋण लेकर अधिक उत्पादन करता है। नई फैक्टरी लगाता है। नई फैक्टरी के उत्पादन को प्रॉफिट में बेचकर ऋण पर ब्याज अदा करता है। ध्यान देने की बात है कि यह सुचक्र मांग से शुरू होता है। यदि बाजार में मांग होती है तो उद्यमी किसी न किसी तरीके से उत्पादन बढ़ा ही लेता है, जैसे वह अपने क्रेता से एडवांस ले लेता है अथवा परिजनों से ऋण ले लेता है। यही सुचक्र मांग के अभाव में स्थापित नहीं होता है। बाजार में मांग नहीं है, छोटे उद्योगों को यूं ही घाटा लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में वह ऋण लेकर लॉकडाउन को तो पार कर सकता है, लेकिन तीन माह के बाद उस पर ऋण का बोझ बढ़ जाएगा, जबकि बाजार की परिस्थिति पुराने स्तर पर भी आ गई तो भी उसमें सुधार नहीं होगा। जैसे पहले यदि उद्योग अपना माल 100 रुपए में बेच रहा था तो लॉकडाउन के बाद वह पुनः 100 रुपए में ही बेचेगा, लेकिन उसके ऊपर ऋण का बोझ बढ़ जाएगा।

कुछ वर्ष पहले मुझे किसी गांव में किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा भैंस खरीदने के लिए दिए गए ऋण का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने ऋण लिया, भैंस खरीदी, दूध बेचा और उनके जीवन स्तर में सुधार आया। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि आप यह बताइए कि आपके गांव में कुल भैंस की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो स्पष्ट उत्तर मिला कि भैंस की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। अर्थ हुआ कि ऋण से केवल टोपी बदली जा रही थी। एक व्यक्ति ने अपनी भैंस को दूसरे को बेचा, उसने तीसरे को बेचा और सभी ने स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया। भैंसों की संख्या वही रही। गांव में दूध का उत्पादन उतना ही रहा। गांव वालों की आय भी उतनी ही रही, लेकिन गांव पर ऋण का बोझ बढ़ गया। उन्हें अब बैंक को ब्याज भी देना पड़ रहा था। पूर्व में उतनी ही भैंसों से जो आय हो रही थी, वह गांव के लोगों को मिलती थी। आज उतनी ही भैंसों से जो आय हो रही है, उसका एक हिस्सा बैंकों को ब्याज के रूप में जाने लगा। गांव वालों की आय कम हो गई। अतः यदि बढ़ी हुई मांग और उत्पादन के अभाव में ऋण दिया जाता है तो उससे जीवन स्तर में गिरावट आती है। आज हमारे छोटे उद्योगों की परिस्थिति ऐसी ही है। उनके सामने उत्पादन पूर्ववत ही है, जबकि ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में छोटे उद्योगों को ऋण देने में बैंक कर्मियों का बोझ भी बढ़ जाता है। कागजी कार्यवाही बढ़ जाती है। अंत में परिणाम यही होता है कि छोटे उद्योगों पर बोझ बढ़ गया। दूरदराज के इलाकों में बैंक कर्मियों को वैसे ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इनके ऊपर यह अतिरिक्त कार्य का बोझ भी आ पड़ता है। इस परिस्थिति में सरकार को छोटे उद्योगों को ऋण देने के स्थान पर उनके द्वारा बनाए गए माल की मांग में वृद्धि करने के उपाय करने चाहिएं। यहां हमारी दो समस्याएं हैं। पहली समस्या विश्व व्यापार संगठन की है। हमने वचन दे रखा है कि हम आयातों पर आयात कर एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाएंगे। इस कारण चीन और दूसरे देशों में बनने वाला सस्ता माल हमारे देश में प्रवेश कर रहा है और हमारे छोटे उद्योगों की हालत खराब हो रही है। इसलिए सर्वप्रथम सरकार को विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत रहते हुए जो आयात कर की अधिकतम सीमा है, उस स्तर पर आयात कर आरोपित कर देना चाहिए। यदि इसके बाद भी छोटे उद्योगों को राहत न मिले तो हमें विश्व व्यापार संगठन से बाहर आने का साहस रखना चाहिए। लेकिन केवल आयातों पर सख्ती करने से बात नहीं बनेगी। यदि अपने देश के बड़े उद्योग उसी माल को बना कर बाजार में बेचते रहे तो छोटे उद्योग पूर्ववत संकट में ही रहेंगे। छोटे उद्योगों की उत्पादन लागत ज्यादा आती है। उनके पास तकनीकी क्षमता कम होती है और छोटे स्तर पर उत्पादन करने से उसमें ईंधन आदि की खपत ज्यादा होती है। अतः प्रश्न यह उठता है कि हम छोटे उद्योगों को समर्थन क्यों दें, यदि उनके द्वारा माल महंगा बनाया जा रहा है? इसका पहला कारण यह कि छोटे उद्योग हमारे देश की उद्यमिता के विकास की प्रयोगशालाएं हैं। दूसरा यह कि इनके द्वारा रोजगार अधिक उत्पन्न किया जाता है और रोजगार उत्पन्न होने से समाज में अपराध की प्रवृत्ति कम होती है। सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं का बोझ कम होता है। तीसरा यह कि छोटे उद्योग कम ही सही लेकिन कुछ तो टैक्स अदा करते हैं जबकि इन्हें बंद कर दिया गया तो बेरोजगार हुए कर्मियों के लिए सरकार को अपने कल्याणकारी खर्च बढ़ाने पड़ेंगे। मेरा मानना है कि उद्यमिता, रोजगार और राजस्व के लाभ को जोड़ कर छोटे उद्योगों के महंगे माल को ही देश को खरीदना चाहिए। सरकार को बड़े उद्योगों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए। यदि कुछ उत्पादों को छोटे उद्योगों के लिए पहले की तरह आरक्षित कर दिया जाए तो भी उनकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो वे स्वयं अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजी जुटा लेंगे। इसलिए उन्हें अतिरिक्त ऋण के बोझ से दबाने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होगा।

गांव, गरीब और कोरोना महामारी

डॉ. राकेश राणा, लेखक

इस महामारी की मार साधारण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि कोरोना संकट के चलते दुनियां में लगभग ढ़ाई करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र में इसके भयवाह परिणाम होगें। इसके बाद जो संकट पैदा होने जा रहा है उसकी भयावहता का अनुमान लगाना और उन तनावों को झेलना दुनियां के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है। जिसका सामना सिर्फऔर सिर्फआपसी सहयोगात्मक व्यवस्था खड़ी करके ही करना संभव है। विश्वव्यापी इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी की इस समय की सबसे बड़ी जरुरत है। तभी इस संकट से उभर पाना दुनियां के लिए संभव होगा। अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति के जरिए ही वैश्विक बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। सबसे बड़ी जरुरत तो किसान-मजदूरों की सुरक्षा है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं गहरे दबावों में आ गई है। इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को संभाला जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए वैश्विक बेरोजगारी को बढ़ने से रोका जाना ही एक प्रभावी उपाय है। लॉकडाउन यानि पूर्ण तालाबंदी करना। यह आपात् व्यवस्था कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। लॉकडाउन के कारण लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह तितर-बितर हो गया है। लोगों का ऐसी परिस्थितियों को समझना मुश्किल है क्योंकि ऐसे संघर्षो के हम अभ्यस्त नहीं होते है और जब संकट मानवीय अस्तित्व पर ही आ खड़ा हुआ हो तो कुछ भी निर्णय करना भारी है।

देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है और कुल रोजगार का 43 प्रतिशत आज भी कृषि से ही आता है। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत दबाव झेल रही है। अब इस महामारी की सीधी मार उसकी कमर तोड़ देगी। नतीजतन देश में महंगाई और बेरोजगारी दोनों परवान चढ़ेगी। जिसका परिणाम होगा विकास दर गिरेगी ही। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम पूरी दुनियां को झेलने पड़ेगें। इस संकट का सबसे गंभीर परिणाम किसान और मजदूर तबके के गरीब परिवारों को झेलना पड़ेगा। जो इस संक्रमण से सीधे प्रभावित होगें, उन पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भयावह होगे। जो सदमा यह संक्रमाण उन परिवारों और व्यक्तियों को देकर जायेगा उससे उभरने में लम्बा समय तो लगेगा ही जिसका परिणाम होगा कि वे भारी मनोवैज्ञानिक दबावों में जीनें को अभिशप्त होगें। हालाकि भारत सरकार ने किसान-मजदूर तबके को राहत देने वाले कदम उठाए है। अभी 20 लाख करोड़ रुपए का 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' पैकेज एक बड़ी और सार्थक घोषणा है। अब सवाल इस पैकेज के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचने का है। इसके लिए एक व्यवहारिक रोडमैप बनाने का है जिसके केन्द्र में किसान-मजदूर वर्ग रहे। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7.92 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 15,841 करोड़ रुपये की राशि पहले से ही हस्तांतरित कर रही है। सभी किसानों को प्रत्येक वित्त वर्ष में दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये की सहायता दी जाने की रणनीति भी राहत भरी है। क्योंकि नकद धनराशी ही समाज को फौरी राहत का एक प्रभावी माध्यम है। सरकार का यह फैसला सराहनीय है। वहीं संकट के समय में इस धनराशी को कुछ और बढ़ाया जाना समय की जरुरत है।

वही कोरोना लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए 4431 करोड़ रुपए 10 अप्रैल तक सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी में वृद्धि करना भी एक बड़ी पहल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत मजदूरी में वृद्धि एक अप्रैल से लागू हो गई। जिसके तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 182 रुपए से बढ़कर प्रति दिन 202 रुपए की गयी है। मनरेगा स्कीम में 13.62 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं। जिनमें से 8.17 करोड़ जॉब कार्ड धारक सक्रिय हैं। इस वर्ष मनरेगा के तहत 18 करोड मानव दिवस सृजित किए जाने की योजना हैं।

जहां कोरोना वायरस महामारी के चलते कहीं भी निकलने और कुछ भी करने पर पूरी तरह रोक है। अभी भी महिनों तक सब कुछ बंद है ऐसे में ग्रामीणों को राहत देने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने ही होगे। इसके साथ ही मनरेगा धनराशी में सरकार को थोड़ा इजाफा करने दिशा में सोचना होगा। साथ ही ग्रामीण मजदूरों के लिए कार्य-दिवसों की संख्या भी दोगुनी होनी चाहिए। तभी इस भयावह परिस्थिति में ग्रामीण लोग अपनी मनःस्थिति को संतुलित करने की तरफ बढ़ सकेगें। इस समय ग्रामीण भारत को आर्थिक संबल की भारी जरुरत है। क्योंकि इस विश्वव्यापी लॉकडाउन में श्रमिकों के पास कोई काम नहीं बचा है,न ही इस वर्ग के पास कोई जमा पूंजी होती है।

कोरोना आपदा और लॉक-डाउन से जूझते बेरोजगार मजदूर और गांव के किसान इस संकट से उभरने के लिए सरकार और समाज के सहयोग पर ही पूरी तरह निर्भर करेगें। विकासशील देशों में इस महामारी के संकट कुछ अतिरिक्त रुप से दर्ज होत दिखायी देगें। जैसे भारत में प्रवासी मजदूरों का मामला लम्बें समय तक सामाजिक-राजीनतिक प्रभाव डाल सकता है। मौजूदा परिदृश्य भारत में सरकारों को अपना पुनरावलोकन करने और अपनी नीतियों तथा सुरक्षा कार्यक्रमों पर पुनर्विचार को विवश करने की दिशा में दबाव बनाने वाला साबित होगा। हमें अपने शहरों को सुरक्षित और संवहनीय बनाने की दिशा में भी मजबूर करेगा। प्रवासी मजदूरों के लिए यह संकट कई तरह की विकट परिस्थितियां खड़ा करने वाला साबित हुआ। उनका रोजगार छुट गया, उनके मन में अपने शहरों को लेकर असुरक्षा का भाव बढ़ा है। इससे उनमें सरकारों के प्रति उदासीनता उभरेगी। उन पर अपने विस्थापन और पुनःव्यवस्था का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। आर्थिक रुप से वे एक चरमरायी स्थिति में जिन्दगी को पुनःगठित करने के दुस्साहसों से जूझते हुए जिन तनावों, अभावों और नकारात्मक प्रभावों के शिकार होगें, वे उनके जीवन को बहुत मुश्किल बनाने वाले साबित होगे। तनाव, निराशा, कलह, और कर्ज जिस तरह का एक उत्पीड़क परिदृश्य विकसित करेंगे। वह स्थायी बनेगा तो समाज में ढ़ेरो विकृत्तियां आयेंगी। कोरोना संक्रमण समाज को गंभीर संकटों में डालने वाला साबित हो सकता है। इस विकट परिस्थिति का सामना हम सब मिलकर ही कर सकते है। समाज और सरकार जितना जल्दी मिलकर एक मजबूत सहयोगात्मक व्यवस्था बनायेंगें उतना जल्दी ही इस संकट से सहज ढ़ंग से हम उभर पाएगें।

केंद्र सरकार कितनी लापरवाह कोरोना संक्रमण में

डॉ.अरविन्द प्रेमचंद जैन, लेखक

हमारे देश में असत्य का बोलबाला हैं जब गंगोत्री ही अपवित्र हो कि हैं तब गंगा कहाँ तक पवित्र होगी ।जब मुखिया ही असत्य का सहारा लेकर अपनी बात की पुष्टि करता हैं तब उस देश की राष्ट्रीय भाषा असत्य बन जाती हैं ।हम कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में हमारे मुखिया को जनवरी 2020 में अधिकृत जानकारी मिल चुकी थी उसके बाद 15 जनवरी से 23 मार्च तक 78 लाख यात्री हवाई यात्रा से आये और उनमे से मात्र 15 लाख की जाँच हुई ।इस दौरान भारत सरकार विदेशियों के स्वागत में लगी रही ,इसी दौरान प्रधान सेवक के निकटम मित्र ट्रम्प साहब की भारत यात्रा के समय पलक पांवड़े से स्वागत किया गया ।राज्य सरकारों ने भी पूरी उदासीनता दिखाई

इसी दौरान भारत ने विदेशों को पी पी इ किट और मास्क का निर्यात किया गया ,इस पर भी प्रधान सेवक ने जन मन बात में झूठ बोला।घटिया किस्म के रैपिड टेस्ट किट्सभी चीन द्वारा प्रदाय किया ।

22 मार्च को बिना पूर्व योजना के लॉक डाउन की घोषणा करने के बाद करोड़ों प्रवासी मजदूरों के बारे में भयावह स्थिति को नजरअंदाज किया गया ।इसी समय जो जहाँ रुका ,वही का होगया। मजदूरों की नौकरी ,मजदूरी छूटी उसके बाद उनको अपने घरों की सुध आयी ,पर उस समय संक्रमण की स्थिति देश में नगण्य थी तब विशेष ट्रेनें बसों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था बनाकर उनको उनके मन मुताबिक स्थानों में भेज दिया जाता जिस कारण राज्यों की अपनी जिम्मेदारी कम होती और लाखों पैदल और अन्य साधनों से जाने से बच जाते ।इस दौरान सरकरों द्वारा किये कामों के अनुपात में निजी संस्थाओं ने सहयोग न दिया होता तो भूख से मरने वालों की संख्या और अधिक होती ,देर आये दुरुस्त आये ।जो मर गए ,जिन्होंने जो अकथनीय वेदनाएं सही हैं उसका मात्र क्षमा और उनका सहयोग मान लिया जाय ।

चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम किया जिससे हजारों मरीज इलाज से स्वस्थ्य हुए और जिनको मरना था वे अपनी लापरवाही से मरे ।और जो भविष्य में बीमार होंगे वे भी अपने कारणों से । वैसे सरकारों ने लॉक डाउन के पहले कुछ समय देकर यह जानकारी के साथ सुव्यवस्था करते की जिनको जहाँ जहां जाना हैं उनकी व्यवस्था कर दी गयी हैं तो पलायन के दौरान इतनी वीभस्त स्थिति न बनती ,वर्तमान में प्रत्येक पलायन करने वाले मजदूरों की लग लग कहानियां दुःख से भरी हैं ।

इसके बाद धार्मिक स्थानों में बंदिश लगाकर बहुत हितकारी काम किया पर बाद में शराब की दुकानों में भीड़ के कारण जोव्यक्तिगत दूरियां की कमी देखी गयी उससे बहुत सीमा तक गलत सन्देश देश में गया।

वर्तमान में देश का आर्थिक पहिया स्थिर हैं और उसको गतिमान बनाने में बहुत समय लगेगा ।कारण कुशल कारीगर जिन्हे हम मजदुर कहते हैं उनके आभाव में उद्योगों को बहुत समय देना होगा ।कार्यकुशलता का प्रभाव पड़ेगा।

हर सिक्के के दो पहलु होते हैं और कोई भी सरकार जनता को खुश करने नहीं बैठी हैं ,सरकारें काम कराने रहती हैं ।उनके अधिकारी कर्मचारियों के अलावा जन सहयोग बहुत अपेक्षित होता हैं ,वह किया गया जिस कारण ही इतनी सफलता मिली या मिल सकी।

जिस प्रकार एक बून्द दही के कारण पूरा दूध खराब हो जाता हैं ,उसी प्रकार प्रधान सेवक ने लॉक डाउन लगाने के पहले कम से कम दस दिन में प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गंतव्य पर पहुंचा देते तो बहुत अधिक सराहनीय कृत्य होता ,अब इतनी विपदाओं के बाद की गयी व्यवस्थाओं से ग्रामं क्षेत्रों में भी संक्रमण से बचा जाना मुश्किल होगा ।और जो आर्थिक जड़ता हुई है उससे उबरना सरल नहीं होगा ।

जैसे समाचार आरहे हैं आगामी काल और भी अधिक कठिन और परीक्षा प्रधान होंगे ,इसमें जन सहयोग के साथ निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।वर्तमान में पेट के साथ अस्तित्व की लड़ाई मुख्य हैं ।इस समय मीडिया की भूमिका भी सराहनीय के साथ भ्रामक होने से उसे भी नियमों के अंतरगत रहकर कार्य संपादन करना चाहिए ।

जनता मात्र मौत के डर के कारण सहयोग दे रही हैं अन्यथा हम इंडियन नियमों को तोड़ने में विशेषज्ञ हैं। भविष्य सुखद होगा यह मंगल कामना करते हैं।

मीडिया पर कोरोना का कहर

डॉ. चंद्र त्रिखा
वरिष्ठ साहित्यकार-पत्रकार

भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संकट में है। कोरोना का कहर सिर्फ प्रवासी श्रमिक-त्रासदी तक सीमित नहीं है, इससे चरमराने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रों के अलावा मीडिया का क्षेत्र भी शामिल है। यह चौथा स्तंभ इस समय गंभीर चुनौतियों का शिकार है। प्रिंट मीडिया यानी अखबारी दुनिया क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट प्रसार व वितरण को लेकर आया और दूसरा बड़ा संकट विज्ञापन-राजस्व में एकाएक आई गिरावट से जुड़ा है। निजी क्षेत्र में बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों ने अपने-अपने विज्ञापन-बजटों में भारी कटौती कर दी, दूसरी ओर सरकारी विज्ञापनों का बजट भी गड़बड़ा चुका है। इस संकट का बुरा असर छोटे समाचार-पत्रों पर तो स्वाभाविक था ही, बड़े-बड़े समाचार समूहों पर भी पड़ा और उन्होंने दो फैसले तात्कालिक प्रभाव से लागू किए। पहला फैसला मीडिया कर्मियों के वेतनों में कुछ कटौतियों का था, दूसरा फैसला तत्काल प्रभाव से समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या में कमी का था। 'आउटलुक' सरीखी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को तो कुछ समय के लिए अपना मुद्रण-प्रकाशन स्थगित भी करना पड़ा। एशिएन एज, डक्कन क्रॉमिकल और डीएनए सरीखे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों को विवश होकर अपने कुछ संस्करण भी अनिश्चित समय के लिए बंद करने पड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जहां विभिन्न उद्योगों के लिए कुछ राहतें घोषित कीं, वहां मीडिया-उद्योग को छुआ तक नहीं। कुछ दबावों व अपीलों के बाद न्यूज प्रिंट पर पांच प्रतिशत कस्टम ड्यूटी की रियायत दी गई। मगर वह रियायत भी विज्ञापन-बजट में कटौतियों के दृष्टिगत हवा हो गई। लॉकडाउन के मध्य प्रिंट मीडिया के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत एक अफवाह प्रचारित की गई कि अखबारों के न्यूज प्रिंट से कोरोना फैल सकता है। प्रिंट मीडिया के लोगों को इन अफवाहों के निराकरण के लिए भी विशेष अभियान चलाने पड़े। भारतीय समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 को भारतीय पत्र-पत्रिकाओं की कुल संख्या एक लाख 18239 थी। इनमें 17573 समाचार पत्र और लगभग एक लाख 666 पत्र-पत्रिकाएं शामिल थीं। 'दि पिच मेडीसन एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट 2020' के अनुसार कुल मीडिया में 20446 करोड़ का विज्ञापन-रेवेन्यू अपेक्षित था। मगर सारे अनुमान हिल गए। भारत में इस समय 900 के लगभग टीवी चौनल हैं। इनमें से लगभग 55 प्रतिशत समाचार-चौनल हैं। शेष 45 प्रतिशत मनोरंजन चौनल पुराने कार्यक्रम दोहराने पर मजबूर हैं। नए कार्यक्रमों की शूटिंग नामुमकिन हो चुकी है। एक प्रमुख चौनल के एक केंद्र को 'कोरोना संक्रमित' होने के संदेह में 'लॉकडाउन' का शिकार होना पड़ा है। उसके लगभग सभी कर्मी अब क्वारंटाइन में हैं। यही स्थिति ऑनलाइन डिजिटल मीडिया की भी है। बहुत सारी वेब साइट्स बंद हो चुकी हैं। टीआरपी बनाए रखने के लिए कुछेक चौनलों को अपने पुराने कार्यक्रमों पर लौटना पड़ रहा है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर संकट का एक कारण विज्ञापन-बिलों की अदायगी का रुक जाना भी है। सिर्फ केंद्र सरकार की ओर से ही 435 करोड़ रुपए की अदायगी रुकी हुई है। यही स्थिति शेष राज्य सरकारों की है। मीडिया की दुनिया में केंद्र या राज्यों की सरकारों के अनुदानों की घोषणा मुमकिन नहीं है। मगर कोरोना संकट से मुक्ति के इस दौर में तीन बातों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना सकती है। पहली, रुकी हुई विज्ञापन राशियों की तत्काल अदायगी हो। दूसरी, नए विज्ञापन-बजट में पांच से दस प्रतिशत की वृद्धि हो। तीसरी, न्यूज प्रिंट पर कस्टम ड्यूटी और घटाई जाए। इन दिनों हमारे देश में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सबसे बड़ी देन व उपलब्धि यह है कि मीडिया ने रिपोर्टिंग में पूरी तरह संयम बनाए रखा। जिस मीडिया को अक्सर प्रतिपक्ष के कुछ नेता 'गोदी-मीडिया' कहने लगे थे, उस मीडिया ने भी निष्पक्षता, तटस्थता और प्रामाणिकता बनाए रखने के ही प्रयास किए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के संवाददाताओं, फोटोग्राफरों ने पूरा-पूरा जोखिम उठाकर फील्ड में रिपोर्टिंग की। सरकार-विरोधी मीडिया ने भी इस अवसर पर अपने पाठक, श्रोता एवं दर्शक को यथासंभव प्रामाणिक सामग्री परोसने की ही कोशिश की। पूरे विश्व की पत्रकारिता में यह एक अनूठा उदाहरण रहा। प्रिंट मीडिया की आर्थिकता दरअसल विचित्र रही है। किसी भी उद्योग में ऐसा नहीं होता कि उसका बिक्री मूल्य उसकी उत्पादन लागत का एक-चौथाई भी न हो। कोई एक सचित्र, बहुरंगी, 12-16 पृष्ठ का दैनिक समाचार पत्र बाजार में ग्राहक अथवा पाठक के पास भले ही तीन रुपए में पहुंचता हो, मगर उसका उत्पादन मूल्य आठ से 10 रुपए तक होता है। अखबारों के संचालक कोशिश करते हैं कि यह अंतर विज्ञापनों से पूरा हो। विज्ञापन या तो सरकारें देती हैं या निजी उद्योग। सरकारों में विज्ञापनों पर नियंत्रण रखने वाले संस्थानों से विज्ञापनों की प्राप्ति और बिलों की वसूली भी सीधे रूप में नहीं होती। बिचौलिए भी होते हैं और नखरे वाले बाबू भी। केंद्र व राज्य सरकारों से मोटे तौर पर अखबारों को लगभग 20-22 हजार करोड़ रुपए की राशि अभी भी वसूलनी है। इनकी तात्कालिक अदायगी की शुरुआत यदि न हुई तो अनेक अखबार पूरी तरह बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। इस संबंध में यदि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के लोकसंपर्क विभाग यदि कोई ठोस उपाय नहीं करते तो लोकतंत्र के इस महत्त्वपूर्ण चौथे स्तंभ पर गंभीर संकट छा सकता है। निर्भीक, निष्पक्ष और प्रामाणिक मीडिया लोकतंत्र की मजबूती की अनिवार्य शर्त है। इस बात की गंभीरता को सरकारी तंत्र को भी समझ लेना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी। मीडिया पर इतना संकट तो आपातकाल में भी नहीं आया था। वैसे भी हर स्तर पर जिंदगी अब मीडिया के बिना चल नहीं पा रही। जब यह दिमागी खुराक का अभिन्न अंग है और सही सूचना का एकमात्र स्रोत है तो उसे बचाने के लिए भी तत्काल फैसले लिए जाने चाहिए। कोरोना-काल में नागरिकों के प्रति जो जिम्मेदार भूमिका भारतीय मीडिया ने निभाई है, उसके मद्देनजर कलम, कैमरा और 'माउस' के इन योद्धाओं के लिए भी सलामी तो बनती है।

नकारात्मक विचारों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह पीड़ादायक होती है

जिसके पास जो होता है, वह केवल वही दूसरे को दे सकता है। इसके मर्म को समझने के बाद आप विनम्र होने लगेंगे। आप अपने अंदर विष नहीं भर सकते हैं। आसपास के लोगों की दुर्भावना दूसरों के लिए पीड़ा देने वाली होती है। उनका दिमाग अशांत होता है। इस कारण वे अशांति फैलाते है। कई बार हम इस पीड़ा को हफ्तों, महीनों तक झेलते रहते हैं और यह हमें आंतरिक रुप से दुखी कर देता है। हम इसे एक झटके में यादों से निकाल नहीं सकते हैं। यह आंतरिक दुख हमारी खुशियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। इससे दुर्व्यवहार का अनुभव पुनर्जीवित हो उठता है, जिससे हम आंतरिक रूप से खोखले हो जाते हैं। उन पलों का दोबारा अनुभव करते हुए हमें उन दुर्व्यवहारों को अपने अंदर पालने या उनको निकाल सकने में से किसी एक को चुनना होगा। उन पलों के एक-एक करके दोबारा जीवित होने पर हम पीड़ा क्यों महसूस करते हैं? विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक विचारों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह पीड़ादायक होती है। एक दुखात्मा दुनिया को कष्ट के नजरिये से ही देखती है। अपने कष्ट के नजरिये से ही देखती है। अपने कष्ट को थामने के लिए दुखात्मा हर संभव प्रयास करेगी। यह उसके अस्तित्व का प्रश्न जो है। वे आपको कष्टमय होने के लिए प्रेरित करती है। इन सबके पार जाने के लिए आप अपने अंदर , परमानंद भाव को उत्पन्न कर सकते है। आपके अंदर भौतिक शरीर के अतिरिक्त प्राणिक तत्व, श्वसन तत्व, मानसिक तत्व, बौद्धिक त्तव और परमानंद तत्व के रूप में पांच परते है। हमारे भीतर मौजूद सभी परतों में ऊर्जा है। यह अंतर्निहित शक्ति के रूप में है। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी में अप्रकट आग होती है और घिसने मात्र से यह जल उठती है। आपको व्यायाम, योग, नृत्य और संतुलित भोजन के जरिये भौतिक शरीर को जगाना होगा। शरीर को चौतन्य और जागृत रखिये। तभी आप अपने पूरे शरीर में प्रसन्नता की ऊर्जी को प्रज्वलित कर पाएंगे।

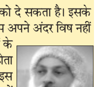

राजनीति के वायरस की गति कोरोना से भी तेज

ओमप्रकाश मेहता लेखक

भारत की मौजूदा राजनीति ने हाल ही में एक बार फिर यह देश को महसूस करा दिया कि राजनीति के वायरस की गति के सामने कोरोना वायरस की गति कोई महत्व नही रखती। राजनीति का वायरस कोरोना से भी अधिक घातक है और कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार हो सकता है, किन्तु भारतीय राजनीति के वायरस का वैक्सीन दुनिया की कोई प्रयोगशाला तैयार नही कर सकती। पिछले दिनों यह कटु अहसास उत्तरप्रदेश की एक घटना ने करवाया, और एक भाषाय वस्तधारी मुख्यमंत्री की निर्मम राजनीति का पर्दाफाश कर दिया।

वैसे यह राजनीतिक घटनाक्रम किसी से भी छुपा नही है, किन्तु इस घटनाक्रम पर राजनेताओं को छोड शेष सभी के लिए गंभीर चिंतन और मौजूदा राजनीति को लेकर अन्र्तमन से चिंतन जरूरी है।

वैसे तो चीन से उत्पन्न कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान व चिंतित है, किन्तु इस महामारी ने पूरे देश में व्याप्त उन करोडो गरीब मजदूरो को एक ऐसा बैरोजगारी और पलायन का दर्द दे दिया जो काफी कठिन व दुख भरा है। आज एक और जहॉ कोरोना पीडितो की संख्या में लगातार वृद्धि होती ही जा रही है, वहीं देश की सडके व राजमार्ग उन असहाय गरीब और मजबूर मजदूरो से पटी पडी है, जो लॉकडाउन के बाद शहरो से बैरोजगार कर दिए जाने के बाद पैदल ही सपरिवार अपने हजारों मील दूर स्थित गॉवो के लिए निकल पडे। यह सिलसिला पिछले ढाई महीने से जारी है, और इस बीच भूख प्यास और दुर्घटनाओं में कई की जाने भी चली गई है, और पिछले ढाई महीने से भारतीय राजनीति इन भूखे-नंगो असहायों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही बॉट रही है। यही स्थिति केन्द्र सरकार की है जो विशेष रेलो का झुनझुना पकडाकर रोते-बिलखते मजदूरों को बहलाने का प्रयास कर रही है।

इस बीच कांग्रेस की महासचिव श्रीमति प्रियंका वाड्रा ने उत्तरप्रदेश में पैदल विचरण कर रहे असहाय हजारो मजदूरो को अपने गत्वंय तक पहुचाने के लिए एक हजार बसें उत्तरप्रदेश सरकार को उपलब्ध कराने की पेशकश की, राजनीतिक स्पर्धा में प्रियंका का यह कदम कहीं उत्तरप्रदेश में सत्तारूढ भाजपा पर भारी न पड जाए, इसलिए उत्तरप्रदेश सरकार चिटटी अभियान शुरू किया और बाद में कांग्रेस ने प्रवास मजदूरों के जमावाडे वाले स्थलों गाजियाबाद तथा नोएडा के लिए पॉच-पॉच सौ बसें रवाना कर दी, किन्तु पहले तो तकनीकी खामियॉ बताई गई और फिर बस की जगह अन्य वाहन भेजने की शिकायत की गई। उत्तरपद्रेश परिवहन विभाग व पुलिस ने बसो को आगरा की सीमा पर रोक लिया और निर्धारित स्थलो तक पहुचने नही दिया, बसे दो दिन तक आगरा की सीमा पर खडी रही इस बीच प्रियंका ने यह भी पेशकश की कि, यदि उत्तरप्रदेश की सत्तारूढ पार्टी इसे कांग्रेस का प्रचार-प्रसार अभियान मानती है, तो बसों पर भाजपा के बैनर, झंडे लगा दिये जाए, किन्तु बैचारे असहाय मजदूरो को तो उनके घरो तक पहुचाया जाए, किन्तु निर्ममता की सीमा पार कर रही सरकार ने प्रियंका की बात पर कोई ध्यान नही दिया और बसों को निहारते हुए मजदूर बसो के सामने से पैदल ही अपने गंतव्य की और चल दिए और फिर मजबूरी में कांग्रेस को अपनी बसे वापस बुलवाना पडी।

आखिर यह निर्मम घटनाक्रम देश की जनता को क्या संदेश देता है ? इससे यह स्पष्ट नही होता कि देश के हर दुखी-दर्दी वर्ग के लिए सरकारों व उन्हे संचालित करने वाले राजनीतिक दल अपरोक्ष रूप से जनता की बेबसी का मजाक उडा रहे है ? आज जबकि देश दोहरे संकट के दौर से गुजर रहा है, तब क्या ऐसे समय भी सत्तारूढ दलो को ऐसी राजनीति करनी चाहिए ? इस घटनाक्रम ने तो फिर एक बार सिद्व कर दिया कि राजनीति के वायरस की गति के सामने कोरोना वायरस की गति तो शून्य है?

मजदूरों को मजबूर नहीं मजबूत बनाइए

प्रभुनाथ शुक्ल

दुनिया सम्भवतः सृष्टि की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से अबतक लाखों लोग अपना बहुमूल्य जीवन खो चुके हैं। लेकिन हम इस विपदा में भी राजनीति का अवसर खोज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों पर काँग्रेस और राज्य की योगी सरकार के बीच जिस तरह की राजनीति दिखी वह बेहद शर्मनाक है। मजदूरों के साथ इससे भद्दा मजाक भला और क्या हो सकता है। संक्रमण को लेकर हालात इतने बुरे हैं कि महाशक्तियों ने भी घुटने टेक दिए हैं। अभीतक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है और हम राजनीति पर उतारू हैं। यह मतभेद के बजाय यह सरकारों और मानवीयता के लिए परीक्षा की घड़ी है।

जब विश्व स्वस्थ्य संगठन ने साफकर दिया है कि इस महामारी का अंत नहीं दिखता है, इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी सुरक्षा के साथ जीना होगा। यह लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। भारत में यह महामारी तेजी से पाँव पसार रही है। चौथा लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया है लेकिन उसका कोई प्रभाव फिलहाल नहीं दिख रहा है। भारत में एक लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में कोरोना वारियर भी संक्रमण के शिकार हो चले हैं। कई डॉक्टरों और पुलिसवालों की मौत हो गई है। प्रवासी मजदूरों की हालत किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब उसपर राजनीति हो रही है। मजदूरों को घर भेजने को लेकर सरकारें किस हद तक जा सकती हैं, उसका उदाहरण हम पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में देख रहे हैं।

भारत में प्रवासी मजदूरों का पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना काल में रोजगार छिन जाने से इस वक्त सबसे अधिक मजदूरों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया है। जिसकी वजह से मजदूर शहरों से पलायन कर रहे हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं रह गया है। धंधे बंद हो गए हैं। कमरे का किराया देने के लिए पैसा भी नहीं है। लोगों में इतना भय और डर समा गया है कि अब जीवन बचना मुश्किल है। जिसकी वजह से लोग शहरों से अपने गाँवों की तरफलौट रहे हैं। गाँव सबसे सुरक्षित ठिकाना लगने लगा है क्योंकि इस वक्त हर व्यक्ति के सामने जीवन बचाने की चुनौती है।

आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र मुम्बई, सूरत, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, कोलकाता, गुड़गांव, चेन्नई समेत दूसरे राज्यों में उद्योग-धंधे बंद हैं। सरकारें मजदूरों से अपील कर रही है कि वह शहर न छोड़ें लेकिन कोरोना का फैलता संक्रमण और उनमें समाया डर उन्हें पलायन को बाध्य कर रहा है। सरकारों ने यह बताने में करोड़ों का विज्ञापन खर्च कर दिया कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, सरकार आपको घर लाएगी। लेकिन वह कैसे रहें जब उनके पास पैसा, भोजन और दूसरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। काम-धँधा बंद होने से उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। हालाँकि सरकारी दुकानों से राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है लेकिन क्या सिर्फ राशन से जिंदगी चल जाएगी। जीवन की दूसरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इस वक्त प्रवासी मजदूर सबसे अधिक मुश्किल में है। जितनी बड़ी चुनौती मजदूरों के सामने है उतनी समाज के दूसरे तबके के साथ नहीं है। इसलिए उन्हें सीधे आर्थिक सहायता की जरूरत है।

प्रवासी मजदूर एक से डेढ़ हजार किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करने को बाध्य हैं। दुनिया में इस तरह की त्रासदी केवल भारत में देखने को मिल रही है। मजदूरों के हौसले की वजह से सड़कें छोटी पड़ गई हैं। लोग माँ-बाप, पत्नी और बच्चों को कंधे पर ढो रहे हैं। गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को ढोने के लिए बैलगाड़ी खींच रही हैं। पिता अपने बच्चों को कांवरी में लेकर लम्बी यात्रा तय कर रहा है। बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर बिहार तक का अंतहीन सफर तय कर रही है। मजबूर मजदूर खुद हाथ गाड़ी बनाकर सैकड़ों किमी की सड़कें नाप रहे हैं। मासूम बच्चे सड़क पर दौड़ती सूटकेस पर गहरी नींद पर सो रहे हैं। लोग भूख और प्यास से तड़प-तड़पकर दम तोड़ रहे हैं। घर आने की जल्दबाजी में अबतक अनगिनत मजदूर सड़क हादसों में अपनी जान गँवा चुके हैं।

प्रवासी मजदूरों पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में काँग्रेस और सरकार के बीच खूब राजनीति देखने को मिली। कौन सच है कौन झूठ यह तो वहीं जाने। लेकिन मजदूरों को क्या हासिल हुआ? शायद इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न काँग्रेस के पास। यह वक्त राजनीति का नहीं है। मजदूरों को सुरक्षित पहुँचाना सरकार, विपक्ष और समाज सबकी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही है। देश के निर्माण में मेहनतकश श्रमिकों के योगदान को भुलाना नाइंसाफी होगी। जब वह हमारे साथ होंगे तभी देश की बुनियाद मजबूत बनेगी। उन्हें मजबूर नहीं मजबूत बनाएं। मजदूरों को लेकर हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं। वक्त रहते अगर हमने कदम नहीं उठाए तो प्रवासी मजदूरों के हालात और बदतर होंगे। हमें पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े होना होगा। अगर उनका भरोसा टूट जाएगा तो हम बेहतर राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर सकते।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

बुरहानपुर में फिर 5 और नए मामले, 24 घंटे में 22 मरीज बढ़े, 294 पहुंचा संक्रमित मरीज का आंकड़ा

माही की गूंज, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण जारी है। सोमवार देर रात आई दूसरी रिपोर्ट में भी 5 और नए मामले आए। कल सुबह की पहली रिपोर्ट में 10 नए मामले आए थे। एक दिन में 15 नए मामले आने से कोरोना संक्रमित 294 मरीज हो गए है। गत 24 घंटे में 22 नए मामले बढ़े है। जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. विक्रमसिंह वर्मा ने बताया कि कल रात की दूसरी रिर्पाट के नए मामलों में 3 पुरूष और 2 महिलाएं है। यह मामले नया मोहल्ला, दौलतपुरा, रास्तीपुरा और ग्राम सिरपुर के है। कोरोना से 13 मौते हुई है। इनमें 4 महिलाएं है। कोरोना संक्रमण के मामले अधिकतर नए हिस्सों से आने से पूरा बुरहानपुर इसके संक्रमण की चपेट में है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य आधिकारी डॉ. एमपी गर्ग ने बताया कि अभी तक 141 मरीज ठीक हुए है। अब 140 सक्रिय मरीज है।

52 वर्षीय संदिग्ध को किया रेफर

माही की गूंज, भीकनगांव। समीपस्थ गांव अंजनगांव के रिछु फलिया में रहने वाले 52 वर्षीय संदिग्ध व्यक्ति को रेफर किया गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने यहां के 40 मकानों में रहने वाले 126 लोगों की स्क्रीनिंग की।

युवक ने फांसी लगाई

माही की गूंज, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में खकनार थाना अंतर्गत ग्राम आमगांव में स्थानीय ग्रामीण युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर दूर हुई है। जांचकर्ता सहायक उपनिरीक्षक चेतन निकुंभ ने बताया कि कल आमगांव में परिजनों के कामकाज पर चले के जाने के बाद धनसिंह भिलाला 25 ने घर में फांसी लगा ली। देर शाम घर लौटने पर परिजनों को इसका पता चला। परिजनों के अनुसार मृतक का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लंबे समय से कामकाज नहीं मिलने से भी वह परेशान था।

अस्पताल में दी 10 पीपीई किट

माही की गूंज, सनावद। नगर के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए पहने जाने वाली पीपीई किट नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दी गई। एसोसिएशन के डॉ विवेक जैन ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अस्पताल में पीपीई किट की आवश्यकता भी रहती है। इस लिए यह दी जाए। जिसके तहत सनावद बडवाह के सिविल अस्पताल में यह किट चिकित्सको को सौपी गई। अस्पताल प्रभारी चिकित्सक डॉ हंसा पाटीदार एसएस मंडलोई विजय कोरी सुभाष बर्डे को एसोसिएशन के राजेंद्र पलोड प्रकाश जैन सुरेश व्यास बीआर अग्रवाल बडवाह ने भेंट की। वही चिकित्सक पाटीदार ने बताया कि अस्पताल में यह किट मिलने से यहां की व्यवस्थाओं में सहयोग मिलेगा। साथ ही कोरोना जैसे संक्रमण के बीच सैंपल लेने के लिए जाने में अब सोहलियत भी मिल सकेगी।

महेश्वर अस्पताल में लगेगी कोविड-19 की दो जांच मशीनें, 12 घंटे में होगी 72 सैम्पलों की जांच

पूर्व मंत्री व विधायक डॉ साधौ ने ली विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक

माही की गूंज, मंडलेश्वर।

कोरोना महामारी के चलते संकट की घड़ी में प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री एंव क्षेत्रीय विधायक डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकार राजस्व सभागृह में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति, मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरों को रोजगार, किसान ऋण माफी योजना, गेंहू उपार्जन एंव समर्थन मूल्य पर खरीदी व बिजली बिलों एंव पानी की समस्याओं सहित अन्य विषयो पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधायक डॉ. साधौ सहित एसडीएम आनंदसिंह राजावत, एसडीओपी मानसिंह ठाकुर, तहसीलदार देवदत्त शर्मा, मंडलेश्वर, महेश्वर के टीआई, बीएमओ, महेश्वर, मंडलेश्वर, करही सीएमओ, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी एसडीओ, विद्युत विभाग एंव खाद्य अधिकारियों सहित अन्य विभागीय अधिकारी मास्क लगाकर उपस्थित थे।

महेश्वर को मिलेगी 2 कोरोना जांच मशीन

कोरोना संकरण से बचाव हेतु पीपीई किट, मास्क, सेनेटाइज की जानकारी लेकर पर्याप्त आपूर्ति हेतु बीएमओ को डिमांड ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए। वही आगामी जून जुलाई में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारियां प्रारम्भ करने पर जोर देते हुए बाहरी जिलों व राज्यों से आने वाले मजदूरों की लगातार जांच करने की बात कही। वही स्वास्थ्य विभाग में महेश्वर अस्पताल में 2 नेट मशीन की सख्त आवश्यकता बताई ताकि कोविड -19 और टीबी जैसी बड़ी बीमारी की जांच करने में आसानी होगी। आवश्यकता को देखते हुए डॉ साधौ ने उच्च अधिकारियों से बात करके मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मशीन उपलब्ध होने से 12 घंटे में करीब 72 मरीजों के सैम्पलों की जांच हो पाएगी। साथ ही मरीजो के सेम्पल इंदौर, भोपाल या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भेजने से जो रिपोर्ट देरी से मिलती है वह मशीन लगने से जल्दी प्राप्त होगी।

नए जॉब कार्ड बनाए ताकि अधिक मजदूरों को मजदूरी मिले-

बैठक में विधायक डॉ साधौ ने मनरेगा योजना पर जोर देते हुए कहा की अभी 3500 मजदूर मनरेगा में काम कर रहे है जो बहुत कम है, संख्या बढ़ाने के लिए लोगों के नए जॉब कार्ड बनाए ताकि उन्हें भी मनरेगा योजनान्तर्ग मजदूरी मिले। इसके साथ अलावा योजनान्तर्ग कपिल धारा कुँए, आंगनवाड़ी, प्लांटेशन, सड़क निर्माण के नवीन निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। लेकिन काम मजदूरों से ही कराए जेसीबी मशीन से नहीं। साथ ही बाहर से आये मजदूरों को खाद्यान्य आवश्यक रूप से दिया जाएं, गेंहू उपार्जन के अंतर्गत किसानों का गेंहू तोलने और खरीदने के आ रही समस्यों को तत्काल दूर करें इसके अलावा जिन किसानों के गेंहू खरीदे गए उन्हें भुगतान किया जाए।

बड़े हुए बिजली बिलों को सुधारे -

बैठक में डॉ. साधौ ने एमपीईबी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की पूर्व में 100 यूनिट बिजली जलाने पर 100 रुपये बिल आता था लेकिन वर्तमान में बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे है। बिलो में उपभोक्ताओं को राहत देकर किस्तों में बिल भुगतान कराएं। और जहाँ ज्यादा बिल आने की शिकायत है उनके मीटर चेक करवाएं।

पेयजल वितरण और सफाई पर दे विशेष ध्यान -

तीनो निकायों के सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा की लॉक डाउन में बाजार और गरीबों की व्यवस्था संभाले। पेयजल और सफाई पर विशेष ध्यान दे। मंडलेश्वर में एक दिन छोड़कर पेयजल वितरण होने पर विधायक डॉ साधौ ने सीएमओ को प्रतिदिन पानी वितरण करने के निर्देश दिए। वही मंडलेश्वर नगर परिषद उपयंत्री के ट्रांसफर के बाद से पद खाने होकर विकास कार्य, निर्माण अनुमति नहीं हो रही जिसपर सीएमओ को महेश्वर या करही के उपयंत्री को प्रभार देकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के भी निर्देश दिए है।

महाराष्ट्र से आये 1.41 लाख से अधिक मजदूरो को 3135 बसो से भेजा गया उनके गृह राज्य तक

माही की गूंज, बड़वानी। लॉक डाउन के मद्देनजर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या मे उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने के इच्छुक मजदूर, बड़ी बिजासन से म.प्र. की सीमा में प्रवेश कर रहे है। विगत 12 मई से अभी तक मध्यप्रदेश की सरकार ने 3135 बसो के माध्यम से 1 लाख 41 हजार 357 मजदूरो को उनके गृह राज्य तक निःशुल्क भेजा हैं। भेजने के पूर्व इन सभी मजदूरो का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुये उन्हें खाना - पानी, मास्क भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है।

सेंधवा एसडीएम श्री घनश्याम धनगर से प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार के दिन 26 मई को प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक 86 बसो के माध्यम से 4 हजार से अधिक मजदूरो को बसो के माध्यम से उनके गणतव्य स्थल के लिये रवाना किया जा चुका है। साथ ही सतत आ रहे मजदूरो की भी स्क्रीनिंग, काउसंलिंग एवं रूट चार्ट अनुसार बसो के माध्यम से भेजा जा रहा है।

लॉक डाउन में बड़ी नॉर्मल डिलीवरी, 2 माह में नही हुई सिजेरियन डिलेवरी

माही की गूंज, सनावद।

सिविल अस्पताल सहित निजी क्लिनिक पर गर्भवती महिलाओं की प्रसूति की जाती है। लेकिन लॉकडाउन के कारण अस्पताल में सुरक्षा की दृष्टि से नार्मल डिलेवरी करवाई गई। जिसमें प्रसूता के साथ आये परिजन भी खुश नजर आए। लॉकडाउन में सिजेरियन डिलीवरी में काफी कमी आई है। कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सक भी नॉर्मल डिलीवरी पर ही जोर दे रहे हैं। उस नजरिए से देखा जाए तो नगर के सिविल अस्पताल में पिछले दो माह में कोई भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। वहीं करीब 300 से अधिक नॉर्मल डिलीवरी चिकित्सकों द्वारा करवाई गई।

यह रहा पिछले 6 माह का रिकार्ड

नगर के सिविल हॉस्पिटल में विगत 6 महीने पूर्व का रिकॉर्ड देखने में आया कि दिसंबर में 155 नॉर्मल प्रसूति हुई थी। जबकि 9 सिजेरियन डिलेवरी करवाई गई हुई। जनवरी में 135 नार्मल प्रसूति 5 सिजेरियन डिलेवरी हुई। फरवरी में 107 नार्मल 6 सिजेरियन डिलीवरी हुई। लेकिन मार्च अप्रैल और मई में सिजेरियन का यह आंकड़ा बिल्कुल नीचे आ गया। मार्च में 117 नॉर्मल 3 सिजेरियन डिलीवरी हुई। अप्रैल में 110 और मई में 93 नार्मल डिलेवरी हुई। चिकित्सक हंसा पाटीदार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण जच्चा और बच्चे की सुरक्षा साथ ही इस संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी रखी गई। यहां पर अधिकतर महिलाओं को नार्मल डिलीवरी करवाई गई। ऐसा पूर्व में भी हुआ था। लेकिन अब कोरोना के कारण किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेते हुए सभी की नार्मल डिलीवरी करवाई गई। जिन चिकित्सको द्वारा पूर्व में सिजेरियन डिलीवरी की गई थी। वह भी प्रमुख रूप से नार्मल प्रसव की सलाह दे रहे हैं। प्रसव से पूर्व प्रसूता की भी की जा रही है। कोरोना लक्षण दिखने पर जांच भी कराने का नियम बना दिया गया है। सिजेरियन के पूर्व डाटा होना अनिवार्य- सिजेरियन में अनिवार्य है प्रसूता का पूरा डाटा प्रसूता या उसके परिवार का कोई सदस्य विदेश यात्रा करने तो नहीं गया। घर के आस-पास कोई संक्रमित नहीं रुका है।

परिजनों का कोई सदस्य किसी कोरोना संक्रमित मिलने वाले से तो नहीं मिला है। प्रसूता को खांसी, जुकाम, बुखार आदि की शिकायत तो नहीं है। करोना वायरस से संबंधित किसी बात पर अन्य बीमारी प्रसूता को नहीं हो। लेकिन चिकित्सकों ने कोरोना काल मे सामान्य प्रसूति करवाकर अच्छी पहल की। वही नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्रसूता के साथ आए परिवार वालों ने भी इसमें सहमति जताते हुए डॉक्टर की बात पर सहमति जताई।

कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 माह में नार्मल डिलेवरी हुई। सिजेरियन केस को इंदौर खंडवा के अस्पताल में रेफर किया गया। वही गुरुवार से सिजेरियन प्रसूति फिर शुरू की जाएगी।

डॉ हंसा पाटीदार प्रभारी सिविल अस्पताल सनावद

गृहे-गृहे गायत्री महायज्ञ श्रृंखला रविवार को

माही की गूंज, सनावद। अखिल विश्व गायत्री परिवार युगतीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में भारत सहित 100 से अधिक देशों में गायत्री साधकों द्वारा लाकडाउन अवधि में गायत्री मंत्र जप महाअनुशष्ठान का क्रम आयोजित किया जा रहा है। साधकों ने 40 दिवसीय अनुष्ठान के अन्तर्गत सवा लाख गायत्री महामंत्र तथा 9 दिवसीय अनुष्ठान के अन्तर्गत 24 हजार गायत्री महामंत्र का जप कर रहे हैं। मंत्र जप का मुख्य उद्देश्य विश्व में फैली कोराना महामारी को समूल नष्ट करने, कोरोना योद्धाओं के उत्तम स्वास्थ्य, उनके उच्च आत्मबल तथा उन्हें अनुकूलता प्रदान करने हेतु वेदमाता, देवमाता माँ गायत्री से प्रार्थना की जाती है।

मीडिया प्रभारी महेन्द्रसिंह पंवार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के गायत्री साधकों ने गाय माता के गोबर से निर्मित कण्डे बनाये हैं जिनका हवन सामग्री के साथ यज्ञ में उपयोग किया जावेगा। युग निर्माण जिला खरगोन के जिला संयोजक पन्नालाल बिर्ला, वरिष्ठ ट्रस्टी पं. रविन्द्र दुबे, डॉ. के.के. श्रीवास्तव, गायत्री शक्तिपीठ सनावद के प्रबंध ट्रस्टी जगदीश शाह, बेड़िया गायत्री शक्तिपीठ के प्रबंध ट्रस्टी भोलेनाथ बिर्ला, तहसील संयोजक डॉ. सोहन गुर्जर ने समस्त साधकों से लाकडाउन को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के साथ समस्त निर्देशों का ध्यान रखते हुये यज्ञ अपने-अपने घरों में अपने परिवार के साथ रविवार को प्रातः 8 से 10 बजे के मध्य में करना है। किसी भी साधक द्वारा कहीं पर भी सामुहिक यज्ञ नहीं करने का अनुरोध किया है।

रजक समाज ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, सनावद। अखिल भारतीय रजक मालवीय धोबी समाज द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया गया। नायब तहसीलदार को दिए ज्ञापन में बताया कि कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। दैनिक आय के माध्यम से अपनी जीविका चलाने वाली धोबी समाज कपड़ों की धुलाई प्रेस करके अपना एवं परिवार पोषण करता है। वर्तमान समय में महामारी के कारण अपने घरों में कैद है। जिससे आर्थिक तंगी के चलते परिवार का पालन पोषण मकान व दुकान का किराया बिजली बिल खाद्य सामग्री पर होने वाला खर्च एवं परिवार का अवश्य खर्चों की भरपाई करने में असमर्थ है। समाज की स्थिति को देखते हुए उत्थान के लिए रजक धोबी समाज को अतिशीघ्र 10 हजार रूपए की राशि प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करें। इस अवसर पर महेश चौहान, बल्लू चौहान, मुकेश मोखले राकेश मालवीय मौजूद थे। ज्ञापन तहसील कार्यलय में नायब तहसीलदार सुखदेव डाबर को दिया गया था।

सफेद सोने की बोवनी में जुटे किसान

माही की गूंज, सनावद। सफेद सोने के नाम से मशहूर कपास उत्पादन में निमाड़ देशभर में पहचान बना चुका है। किसान सफेद सोने की बोवनी में जुटे गए हैं। मालूम हो कि मई के अंतिम सप्ताह मे कपास की बोवनी शुरू हो जाती है। किसान खेत तैयार करने के साथ ही कपास बीज लगाने में जुट गए हैं। इन दिनों खेतों में महिलाएं, युवतियां सहित अन्य खेतों में लाइन लगाकर कपास लगाते हुए आसानी से नजर आ रहे हैं। ढकलगांव निवासी किसान सदाशिव बड़वाला, राहुल केलवावाला, दिनेश चाचरीया, महेंद्र बड़वाला, कमल बड़वाला,जगदीश राड़वा, शुभम संकडिया ने बताया कि पहले बारिश के बाद ही कपास की बोवनी करते थे। कई बार कम या ज्यादा बारिश होने के कारण कपास खराब हो जाता था कपास में बीमारी भी ज्यादा लगती थी। इसके कारण वहां मई में ही कपास लगा देते हैं जिससे बारिश में इस तरह की समस्या नहीं आती है। समीपस्थ ग्राम ढकलगांव साला, ढसगांव, भानबरड़, धनगांव, नलवा, बिजंलवाड़ा, कालधा, बोरूट अंजनगांव सहित अन्य क्षेत्रों में किसान कपास की फसल लगा रहे हैं।

ढकलगांव मे चिलचिलाती धूप मे कपास लगाती महिलाएं।

बगैर मास्क पर 1000 का दंड, भीड़ दिखी तो दुकान होगी सील

माही की गूंज, भीकनगांव। मंगलवार देर शाम साढ़े 7 बजे एसडीएम बीएस सोलंकी ने नगर के व्यापारियों के साथ थाना परिसर में बैठक की। बैठक मे एसडीएम सोलंकी ने दुकानदारों को दुकान पर 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करने की हिदायत दी। इसका उल्लंघन होने पर नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ मनोज गंगराड़े को दुकानदार की दुकान 7 दिनों के लिए सील किए जाने के निर्देश भी दिए। दुकानदारों को दुकान के बाहर आवश्यक रूप से पांच गोले सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लगाने का भी कहा गया है। वही नगर में यदि कोई व्यक्ति बगैर मास्क के घूमते पाए जाने पर 1 हजार की चालानी कार्यवाही करने की बात भी कही। सब्जी और फल विक्रेताओं को भी किसी एक स्थान पर दुकान, ठेले या बैठक से सब्जी या फल विक्रय नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। फल विक्रेताओं को केवल फेरी के माध्यम से ही सब्जी और फल बेचने की अनुमति होगी। इस दौरान एसडीएम सोलंकी ने सब्जी और फल विक्रेताओं को अमनखेड़ी रोड पर स्टेडियम में व्यवस्था करने पर विचार करने की बात कही। निर्देशों के साथ एसडीएम ने स्पष्ट किया कि, नगर व क्षेत्र में होटल व पान की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जाएगी। बैठक में तहसीलदार देवकुंवर सोलंकी, नायब तहसीलदार ममता मिमरोट, एसडीओपी आरआर अवास्या, थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया सहित व्यापारी उपस्थित थे।

बाहर से लौटे मप्र के मजदूरों को मिलेगा संबल योजना का लाभ

सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन किया जाएगा 27 मई से 3 जून तक

माही की गूंज, बड़वानी।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और कोरोना संकट के कारण 1 मार्च 2020 या उसके बाद प्रदेश में वापस आये है। ऐसे श्रमिको को शासन की विभिन्न योजनाओं के समस्त लाभ देने की दृष्टि से 27 मई से 3 जून तक सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य किया जायेगा। इसके लिये मजदूर को प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।

जिनके पास पहचान पत्र नही उन्हें मिलेगी समग्र आईडी

राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन किये जाने का कार्य नगरीय क्षेत्रो में वार्ड प्रभारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों को दिया है। ऐसे श्रमिक जिनका समग्र आईडी नही है और म.प्र. के मूल निवासी है। ऐसे प्रवासी श्रमिको का समग्र आईडी नियत प्रक्रिया के अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट की जायेगी। साथ ही इनका सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन का कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा। सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन उन्ही प्रवासी श्रमिको का किया जायेगा जो 'मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना' अथवा 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल' में पंजीयन के लिये पात्रता रखते है।

इनका नही होगा सर्वे, सत्यापन, पंजीयन का कार्य

सर्वे के दौरान निम्न श्रेणियों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन नहीं किया जायेगा जो प्रवासी श्रमिक मध्यप्रदेश का मूल निवासी नही है। ऐसे म.प्र. के मूल निवासी श्रमिक जो 1 मार्च 2020 के पूर्व नियोजित राज्य से मप्र में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आये है। साथ ही ऐसे मूल श्रमिको का भी सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन नही होगा, जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गये है।

मिलेगा यह लाभ

इन श्रमिकों को मप्र शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें मनरेगा का कार्य तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जायेगा।

विस्थापित परीक्षार्थी जहां है, वहीं से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे

आगामी 9 जून से होंगी हायर सेकेण्डरी परीक्षाएं

माही की गूंज, खण्डवा।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी व्यावसायिक, हायर सेकण्डरी अंधमूक बधिर की शेष परीक्षायें आगामी 9 जून से आयोजित की गई है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी अनुसार लॉकडाउन अथवा अन्य कारणों से कतिपय परीक्षार्थी अपने निवास के वर्तमान स्थान से अन्य स्थानों पर विस्थापित हुये हैं। मण्डल के सचिव श्री अनिल सुचारी ने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित न हों, इस उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है कि विस्थापित परीक्षार्थी विशेष परिस्थितियों में वर्तमान में जिस भी जिले में निवासरत हैं वहीं से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो कुछ विषयों की परीक्षा मार्च माह में दे चुके है, लेकिन लॉकडाउन के कारण किसी अन्य जिले में फंस गए है, तो वे शेष विषयों की परीक्षायें अन्य किसी जिले से दे सकते है। इसके लिए इच्छुक परीक्षार्थी 25 मई सायं 4 बजे से 28 मई तक ऑनलाइन आवेदन एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क, पोर्टल, मण्डल के मोबाइल एप के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिले के समन्वयक संस्था, मण्डल के संभागीय कार्यालयों के माध्यमों से भी उपलब्ध रहेगी। परीक्षार्थियों को जिला परिवर्तन करने की स्थिति में नवीन चयनित जिले के जिला मुख्यालय पर परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। जिले के भीतर केन्द्र परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

वर - वधु ने समझाया मास्क एवं सेनेटाइजर का महत्व

माही की गूंज, बड़वानी।

ईद के दिन निवाली में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जिसमे ना बैंड बाजा था ना ही घोडा। वही वर - वधु ने फेरे के पहले अपने परिवार के सदस्यों को मुंह पर मास्क लगाने एवं सेनेटाइजर से हाथ धोने का महत्व बताया। जिससे सभी कोरोना वायरस के महामारी से सुरक्षित रह सके।

ईद के दिन सोमवार को निवाली निवासी डॉ जया माली एवं डॉ लोकेंद्र माली का विवाह सादगी के साथ सम्पन्न हुआ। दोनो परिवार के सीमित सदस्यो की उपस्थिति में सम्पन्न इस विवाह के दौरान जहाँ सभी ने मुंह पर मास्क लगाकर रखा था वही सोशल डिस्टेंस का भी पालन करा। वर - वधु ने अपने इष्ट मित्रों से बधाईयाँ भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त कर उनका आभार व्यक्त किया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद पर रात में हो रहा मरीजों की जान से खिलवाड़

रात में ड्यूटी पर से गायब स्टाफ, आए दिन हो रहे लापरवाही के शिकार

माही की गूंज, पेटलावद।

कोरोना संकट काल में आम जनता के बीच भगवान बने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी का दूसरा चेहरा भी सामने आया है। जिसको देख कर भगवान बने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर से ही भरोसा उठ जाए। पेटलावद सामुदायिक केंद्र पर रात में पहुंचने वाले मरीजो में अधिकांश मरीज गंभीर रूप में अस्पताल आते है। ऐसे में अस्पतालों में रात की डॉक्टर और स्टाफव्यवस्था अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन विकासखण्ड के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति होगी इसका पता इससे ही लग जाता है जब विकास खण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था की पोल खुलती हैं। जहां इमरजेंसी में मरीज ठीक होने की बजाए अपनी मौत के करीब पहुंच जाए।

ऐसा ही एक मामला शनिवार रात पेटलावद के शासकीय सामुदायिक केंद्र में देखने को मिला। यहां इतनी भयानक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाए या नहीं। शनिवार रात बदनावर रोड़ कॉलेज के पास हुई दुर्घटना में घायल ड्राइवर का हाल जानने पहुंचे तो पता चला के ड्राइवर का पैर टूट चुका था। उसे और उसके पास एक अन्य मरीज को बॉटल लगी हुई थी। दोनों मरीजों को गंभीर हालत में सीरिंज किसी वार्ड बॉय द्वारा लगाई होगी क्योंकि बेड पर लेटे मरीजों को जानवरों की तरह उन्हें बॉटल की सीरिंज लगाई गई थी। दोनों की बॉटल आउट होकर खून निकलने लगे गया था। रात में ड्यूटी टाइम पर रहने डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं थे। अस्पताल में मौजूद एक मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित था। उसने दोनों मरीजों की आउट हो चुकी बॉटल को देखा तब कहीं जाकर महिला कर्मचारी ने दोनों की बॉटल निकाली।

दोनों ही पेशेंट के हाथों पर बॉटल आउट हो जाने के कारण सुजन आ चुकी थी। एक की तो सीरिंज निकाल देने पर खून बहने लगा। अस्पताल में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं था। उसी कर्मचारी से पूछा की सिस्टर कहां है। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली यही है सिस्टर। कैमरे को देख कर शासकीय अस्पताल में स्टाफ और लापरवाही का शिकार मरीजों के परिजन आकर शिकायत करने लगे।

वही शनिवार रात में ही मारपीट के मामले एक खून से लथपथ महिला को हॉस्पिटल के ड्रेसिंग रूम ले जाया गया। जहां उसे गंभीर हालत में ही डॉक्टर के घर भेजा दिया गया। परिजन बेचारे उस खून से लथपथ महिला को दुपहिया वाहन पर बैठा कर डॉक्टर के आवास पर ले गए। डॉक्टर साहब को जगाया गया। साहब ने महिला की स्थिति और हमारा कैमरा देख पुनः महिला को ड्रेसिंग रूम ले जाने को कहा और खुद भी ड्रेसिंग रूम की तरफचल दिए। शासकीय अस्पताल में जो लापरवाही का आलम हैं उसको देख कर तो यही है कि यहां आम जीवन की कोई कीमत नहीं।

मामले में बीएमओ एमएल चोपड़ा का कहना है कि मेरी जानकारी में मामला आया है। मेरी ओर से सभी स्वास्थ्यकर्मियों को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है। बाकी वीडियो देखकर लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। बीएमओ ने कार्यवाही की बात तो कह दी, लेकिन लगता नहीं की कोई मजबूत कार्यवाही की जाएगी क्योंकि इससे पहले भी यहां मरीजों के इलाज में लापरवाही और गरीब ग्रामीणों से पैसे लेने के गंभीर मामले आए थे। जिन्हें जांच के नाम पर कचरे के ढ़ेर में डाल कर लापरवाही बरतने वालों को आगे भी इस प्रकार की लापरवाही के लिए प्रेरित कर बिना सजा दिए छोड़ दिया गया था।

ईद पर गले नहीं मिले लोग, दूर से दी मुबारकबाद

माही की गूंज, झाबुआ। ईद-उल-फितर का त्योहार मुस्लिम समाज ने सादगी से मनाया। लॉकडाउन के चलते ईदगाह पर 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। जबकि समाजजनों ने घरों में रहकर ही नमाज अदा की। ईदगाह पर सुबह साढ़े 8 बजे पेश इमाम शाने आलम साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज अदा करने के बाद कोरोना खात्मे की दुआएं की गई। लोगों ने नमाज के बाद गले मिलने के बजाए दूर से ही मुबारकबाद दी। इसके अलावा समाजजनों ने घरों में नमाज पढ़ी। इसके अलावा सभी समाजजनों ने घरों पर शीरखुरमा व सिवैयां का लुत्फ उठाया। पर्व को लेकर बच्चों में उत्साह था। वे बड़ो से ईदी लेते दिखाई दिए। अंजुमन कमेटी के जिला सदर नोमान खान ने बताया शासन के दिशा-निर्देशानुसार पांच लोगों ने ही ईदगाह पर नमाज पढ़ी।

सादगी से मनाया ईद उल फितर पर्व

माही की गूंज, पेटलावद। ईद-उल-फित्तर का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह पर सुबह साढ़े 7 बजे नमाज अदा करने के बाद कोरोना खात्मे की दुआएं की गई। बता दे कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वायरस की वजह से त्योहारों की रौनक पूरी तरह से उड़ गई है। लोगों के चेहरों पर उदासी है।

लॉकडाउन के चलते ईदगाह 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। ज्यादातर लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज अदा की। सुरक्षा बतौर तहसीलदार जितेंद्र अलावा, एसडीओपी, टीआई संजय रावत, सीएमओ एलएस राठौड़, पटवारी दुलेसिंह सिंगाड सहित पुलिस अधिकारी दल-बल के साथ मौजूद रहे। वहीं पूरे नगर में भी अलग-अलग टुकडियों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। पुलिस ने लगातार घूम-घूम कर लोगों से शारीरिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाकर बाहर आने की अपील भी की। लोग एक दूसरे को शीर खिलाकर ईद उल फित्तर की मुबारकबाद दिनभर देते रहे हैं। शासन प्रशासन और उलेमाओं की अपील का माकूल असर ईद के त्योहार पर नजर आया।

सोमवार को पूरे देश मे ईद का त्योहार मनाया गया, लेकिन इस वक्त जो देश के हालात चल रहे हैंए उसे देखते हुए लोगो ने इस बार ईद पर गले न मिलकर एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी।

प्रशासन ने होम क्वॉरेंटाइन लोगों को दी समझाइश

माही की गूंज, कुन्दनपुर। ग्राम कुंदनपुर में तहसीलदार और टीआई ने होम क्वॉरेंटाइन किए गए लोगों को घर पर जाकर समझाइश दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों को 14 दिनों तक घर में ही रहना है। किसी तरह की परेशानी आने पर पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों से मदद लें। अधिकारियों के रोड़ पर निकलते ही लोगों ने ने सारी दुकानें बन्द कर ली।

हाट बाजार के दिन कुंदनपुर रहा पूरी तरह बंद

माही की गूंज, कुंदनपुर। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में सभी हाट बाजार वाले दिन बाजार के बंद रहेंगे। इसी आदेश के परिपालन में सोमवार को कुन्दनपुर भी हाट बाजार का दिन होने के बाद भी पूर्णतः बंद रहा। सभी व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। लोगों ने घरो पर ही आराम किया। कई लोगों ने अपने घरों के कामकाज निपटाए और कलेक्टर के आदेश का पालन भी किया।

सुविधाओं का नहीं हो रहा उपयोग

मरीजों को जिला अस्पताल में परेशानी झेलना बन चुकी है नियति

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का अंबार निरंतर बना हुआ है। जहां एक ओर लॉक डाउन के आंशिक छूट के बाद जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वही वार्डों में भर्ती मरीजों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक ओर मई माह की भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी ओर उल्टी, दस्त से परेशान मरीजो को जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को पलंग तक की सुविधा नही मिल पा रही है। जिले भर का सबसे बडा जिला चिकित्सालय केवल नाम मात्र ही रह गया है। असुविधाओं का अंबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं जिला चिकित्सालय में पूर्व में भी अखबारों में प्रकाशन के माध्यम से बताया गया था कि बच्चों के वार्डो में एक ही पलंग पर दो-दो बच्चों का ईलाज किया जाता था। आज वर्तमान में भी यही स्थिति अन्य वार्डों में दिखाई दे रही है कि मरीजों को ईलाज करवाने के लिए पलंग तक नसीब नहीं हो रहे है। ऐसे में मरीजों को जमीन पर सोकर ईलाज करवाना मजबूरी बन गया हैं।

जिला चिकित्सालय में जहां एक ओर ट्रॉमा सेन्टर में एजस्टेबल बेड धूल खा रहे हैं। वही दूसरी ओर मरीज जमीन पर सोने को मजबूर हो रहे है। इनमे कई बेड तो ट्रॉमा सेन्टर में भर्ती मरीजों के लिए ही बुलवाये गये थे। लेकिन इस सुविधा का लाभ ग्रामीण मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। जिला चिकित्सालय की तीसरी मंजिल पर बने प्रायवेट 4 वार्डो में से दो वार्डों को भी टीबी के मरीजों के लिए बना रखा है। जबकि इन मरीजों को तत्काल सुविधा मिलने की जरूरत होती है। ऐसे में यदि कोई टीबी का मरीज भर्ती होता है, तो उसके परिजनों को बार-बार सिस्टर एवं डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। क्योंकि मेल सर्जिकल वार्ड की ही सिस्टर को प्रायवेट के वार्डो को देखना होता है। जिसमें पूर्व से ही 20 से 30 मरीज वार्ड में भर्ती रहते हैं, तो उसे प्रायवेट में कहां समय रह पायेगा। इस पर से रात्रि में भर्ती मरीज को यदि प्रायवेट वार्ड में रखा जाता है तो उसके लिए ओर भी तकलीफबढ़ जाती है। जिस पर से वार्डो से रात्रि में सिस्टर भी आने में कतराती हैं। प्रायवेट वार्ड में एक ही नर्स की ड्यूटी होने के कारण यह सब परेशानियां हो रही है। वहीं जिला चिकित्सालय के आला अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला हुआ है, लेकिन झाबुआ नगर के साथ ही संपूर्ण जिले में अभी स्थिति को कोरोना संक्रमण से बचा रखा है। बावजूद इसके अन्य मरीजों पर ध्यान कम ही दिया जा रहा है।

ट्रॉमा सेन्टर में मरीजों को बिस्तर के अभाव में जमीन पर इलाज करवाना पड़ रहा है।

अतिथि विद्वान करते हैं यूजीसी मापदण्ड पूरा, फिर भी रोजगार से दूर

माही की गूंज, झाबुआ। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लम्बें समय से चली आ रहीं शोषणकारी अतिथि विद्वान व्यवस्था में पढाने वाले नेट, स्लेट, एमफिल, पीएचडी जैसी उच्च योग्यताधारी अपने नियमितीकरण और छः माह से नौकरी से वंछित है। जिससे उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई हैं। शिवराज सरकार द्वारा कोई उचित कदम नही उठानें से मनोबल टूटता जा रहा है। वर्षो से युजीसी के नियमानुसार अध्यापन कार्य करते आ रहें है। परंतु वेतन के नाम पर अल्प मानदेय दिया जाता है। जाँच से वंछित रखकर कांग्रेस सरकार ने सहायक प्राध्यापक भर्ती 2017 से 2700 लोगो को दिसंबर में नौकरी से बाहर कर दिया था, जिसमें से 465 लोगो को फरवरी में च्वाईस फिलिंग से अंदर कर लिया गया, लेंकिन शेष आज तक बेरोजगार है। लगातार शिवराज सरकार से अनुरोध कर रहें है। परंतु अब तक एक भी व्यक्ति को सेवा में नही लिया है।

कमलनाथ शासन में 17 मार्च को हुई आखिरी केबिनेट में अतिथि विद्वान मुद्दे को पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतु पटवारी ने मंत्रिमंडल में भेजने के लिए संक्षेपिका तैयार करवाई थी, जिसकी नोटशीट का जावक क्रमांक 1438 दिनांक 15 मार्च 2020 था। जिसमें यह था कि, जो कार्यरत अतिथि विद्वान युजीसी मापदण्ड पूरा करते है, उनका नियमितीकरण किया जाए, जो नहीं करते है उनको संविदा नियुक्ति देकर चार वर्ष में अनिवार्य शर्त पूरी करने का अवसर दिया जाए तथा मापदण्ड पूरा करने पर उनका भी नियमितीकरण किया जाए। परंतु अधिकारियों ने इसे यह कहकर टाल दिया कि अभी प्रस्ताव तैयार नही है। वहीं केबिनेट नें कई फैसलें लिए थे, परंतु यह नहीं। अब शिवराज सरकार क्या निर्णय देती हैं, इस बात पर सभी उम्मीद लगाएं बैठें है। कोरोनाकाल में अतिथि विद्वान अपने असुरक्षित व अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

स्थानीय पीजी कॉलेज झाबुआ के अतिथि विद्वान शंकरलाल खरवाडिया का कहना है कि, अतिथि विद्वानों की नियुक्ति जरूरी शर्तो से होती है, काम भी सभी करवाया जाता है। लेंकिन वेतन को मानदेय नाम दिया जाता है। इस तरह हमारें भविष्य के साथ वर्षो से खिलवाड़ हो रहा है।

कांग्रेस नेता प्रभात श्रीवास्तव को पितृ शोक

माही की गूंज, पेटलावद। कांग्रेस आईटी सेल के जिला महामंत्री प्रभाव श्रीवास्तव के पिता अशोक कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त प्राचार्य) का मंगलवार सुबह देवलोकगमन को हो गया। जिनका अंतिम संस्कार पेटलावद मुक्ति धाम पर किया गया। लॉकडाउन के चलते ज्यादा लोग अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। विधायक वालसिंह मेडा, जिला उपाध्यक्ष डाबड़ी दरबार, ब्लॉक अध्यक्ष सलूनिया दरबार, विधायक प्रतिनिधि मन्ना हामड, आईटी सेल के विक्रम चावड़ा, ब्लॉक महामंत्री कयूम शेख, वरिष्ठ नेता सुरेश मुथा, जावेद खान, आशीष मुथा सहित कई कांग्रेस नेताओं सहित नगर के समाजसेवियों, नेताओं और नागरिकों ने शोक व्यक्त कर श्रीवास्तव परिवार को ढांढस बंधाया। श्रीवास्तव परिवार विधायक निवास के पास में ही रहता है और विधायक के बेहद करीब माना जाता हैं। प्रभाव श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने भी सेकीं रोटियाँ

संस्था सामाजिक सरोकार के सेवा कार्यो का अवलोकन किया

माही की गूंज, इंदौर।

लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंदो को संस्था सामाजिक सरोकार द्वारा संयोजक श्रीमती सरस्वती पेंढारकर के नेतृत्व में वार्ड 81 में पांचाल धर्मशाला में भोजन तैयार कर वितरण की व्यवस्था लॉक डाउन के प्रारम्भ से ही की जा रही है ।

इस सेवा प्रकल्प का बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने निरीक्षण किया तथा यहां रसोई निर्माण में कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष में बरती जा रही सावधानियों व सफाई व्यवस्था की तारीफ की। यहां सेवाएं देने वाली करीब 20 मातृशक्तियों से मुलाकात की तथा उनके द्वारा की जा रही सेवाओ को सराह तथा हरसम्भव मदद का आश्वासन भी दिया।

मातृ शक्ति के आग्रह पर रोटियां भी सेकीं

अवलोकन के दौरान जब श्री विजयवर्गीय भट्टी के पास पहुंचे तो मातृ शक्तियों ने उनसे रोटी सेंकने का आग्रह यह कहकर किया कि, आप एक रोटी सेंक दो जिसे सारी रोटियों के साथ रख देंगे ताकि सभी प्रसाद के रूप में बंट जाएगी, इस पर श्री विजयवर्गीय खुश हो गए और रोटियां सेकीं तथा यह भी कहा कि आखिर आप सभी ने यह कार्य भी करवा लिया।

वही इस कार्य मे आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को आपसी तालमेल से दूर करने की बात कही ताकि जरूरतमंदों को सेवाएं मिलती रहे। श्री विजयवर्गीय ने यहां स्थित मंदिर में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा व शिवलिंग के दर्शन भी किए। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक जीतू जिराती, भाजपा नेता नीलेश चौधरी सहित वार्ड के कार्यकर्ताओ के साथ संस्था की संरक्षक श्रीमती सरस्वती पेंढारकर, शिवम पेंढारकर आदि उपस्थित थे।

मुनिद्वय का चातुर्मास सेलम तमिलनाडु में होगा

माही की गूंज, झाबुआ। मालव केसरी संयमवय स्थविर वरिष्ठ मुनिराज श्री हितेषचन्द्र विजयजी मासा एवं ज्योतिषरत्न मुनिराज दिव्यचन्द्रविजयजी मासा जिनका चातुर्मास मदुरै मे होना तय किया गया था। किन्तु कोरोना माहामारी के कारण परिस्थितियां परिवर्तित होने से मुनिद्वय ने श्रीमद् विजयऋषभचन्द्र सुरिजी मासा के आज्ञा से तथा मदुरै श्रीसंघ की सहमति से वर्ष 2020 को चातुर्मास आदिश्वर भवन सेलम तमिलनाडु में करना तय किया है। जिसमे मुनिद्वय का मंगल प्रवेश 28 जून रविवार को सेलम में होगा। मुनिद्वय ने समस्त जैन धर्माभिलंबियो से आव्हान किया है कि वे कोरोना वायरस के चलते तथा लॉक डाउन के कारण अपने घरो से मंगल प्रवेश की अनुमोदना करके गुरूभक्ति का परिचय प्रदान करे। उक्त जानकारी ने रिंकु रूनवाल ने दी।

वरिष्ठ फोटोग्राफर भरत त्रिवेदी का देवलोकगमन

माही की गूंज, झाबुआ। गोपाल कॉलोनी स्थित वरिष्ठ फोटोग्रफर भरत त्रिवेदी का सोमवार 25 मई को देवलोकगमन हो गया है। जिनकी अंतिम-यात्रा शाम 6 बजे निवास स्थान से शासन के निर्देशानुसार सीमित परिजनों की उपस्थिति में निकाली गई। घर के बड़े बेटे रितेश त्रिवेदी के द्वारा मुखाग्नी दी गई। प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते वर्तमान परिस्थिति में सभी परीजनों से अपने स्थान से ही श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अपील की। नगर के सभी गणमान्य नागरिकों समग्र मीडिया के द्वारा भरत त्रिवेदी की निधन पर श्रद्धांजली अर्पीत की गई।

पृथम पृष्ठ से शेष

सांसद जी कैसे कहें एक साल बेमिसाल

लॉक डाउन में मिल सकता था रोजगार

कोरोना वायरस के चलते देश में पिछले 65 दिनों से लॉकडाउन हैं। लोग बेरोजगार बैठे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने दूसरे लॉक डाउन के बाद ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के कार्य शुरू कर दिए। वहीं शहरी क्षेत्रों में कोई योजना लांच नहीं की। जिससे शहरी क्षेत्र के कामगारों को मजदूरी मिल सके। ऐसे में यदि सांसद और प्रशासन ने मामले में रुचि दिखाकर 202 मकान के आंवटन की बची कुची कसर पूरी कर राशि आंवटित कर दी जाती तो न केवल लॉक डाउन में फ्री बैठे मिस्त्री, कारीगर, शहरी मजदूर, निर्माण सामग्री से जुड़े व्यापारी, ईंट व्यापारी, सेंटिंग कारीगरों सहित सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते थे। साथ ही फ्री समय में लोगों के मकान बारिश से पहले बनकर तैयार हो जाते, लेकिन किसी का ध्यान इस दिशा में नहीं गया। अधिकारी तो इतने लापरवाह हो गए कि कोरोना के अलावा किसी अन्य मामलों को फाइल को हाथ तक नहीं लगाया।

आखिर क्यों अटकी पड़ी है फाइल

जब इस योजना के अटकने के पीछे के कारण तलाश किए तो एक नहीं कई कारण सामने आए। सांसद के मामले में रुचि नहीं लेने के पीछे नगर परिषद पेटलावद से नाराजगी बताई जा रही हैं, जो कि नगर परिषद के सहयोग से स्वच्छता अभियान पर जारी एक पत्रिका में लगे नगर परिषद की ओर लगे विज्ञापन में सांसद का फोटो नहीं होंने से उपजी थी। जिस प्रकार से नगर परिषद द्वारा पूरी दस्तावेजों की कार्यवाही पूरी होने के बाद भी बार-बार अलग अलग कारणों से फाइल को घुमाया जा रहा है। उसके पीछे कमीशन का खेल भी हो सकता हैं। 202 मकानों के भुगतान को देखा जाए तो राशि लगभग 05 करोड़ तक जाती है। ऐसे में आधिकारिक कमीशन के चक्कर में जानबूझकर लेटलतीफी की जा रही है। जबकि 15 महीने रही कांग्रेस की सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि पेटलावद से लगातार हार और गिरते वोट बैंक के कारण जानबूझकर मकानों की फाइल को रोक कर रखा गया। तो कुछ का कहना हैं कि कई मकानों पर आपत्ति ली गई थी, जिसकी जांच की जा रही है। नगर परिषद के कुछ पार्षदों से भी मामले में बात की तो संगठन के चुनाव और सांसद से मामला जुड़े होने के कारण बोलने से बचते रहे और किसी प्रकार से बयान नहीं दिया।

हो चुका है लगभग कार्य

नगर परिषद के द्वारा जी-जान से हितग्राहियों को लाभ देने के अधिकारियों द्वारा मांगे गए एक एक कागज की पूर्ति की गई। पूरे नगर में कहां-कहां हितग्राहियों को लाभ मिलना हैं। उसका नक्शा तक बनवाया और एक-एक घर का सर्वे जिलाधिकारी के आदेश से प्रशासन स्तर पर किया गया। जिसका प्रतिवेदन लगभग तैयार हो चुका। फिर भी केंद्र की योजना का लाभ लोगों को मिले उसके लिए केंद्र की योजना में रुचि नहीं दिखने वाले सांसद और फाइल लटकाने वाले अधिकारियों को केन्द्रीय नेताओं और मंत्रियो की फटकार जरूरी है। जिससे आगे योजना का लाभ सीधे हितग्राहियों को मिल सके। अब जबकि सब कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शहरी विकास प्राधिकरण झाबुआ का चार्ज एलएस डोडिया सीएमओ झाबुआ से लेकर कमलेश गोले राणापुर सीएमओ को दिया गया हैं। ऐसे में पूरी कागजी कार्यवाही नए अधिकारी फिर अपनी और से बारीकी से जांचेंगे और शायद फाइल में एक बार फिर कोई कमी पेशी निकाली जाए या फिर कलेक्टर कार्यालय के बाबूजी फिर से किसी कमी को निकाल कर फाइल अटका दे। सांसद डामोर को केंद्र की योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर अपने मन से फोटो नहीं छपने की टीस हो, तो उसे निकालकर नगर परिषद का सहयोग करना चाहिये ताकि देश के प्रधानमंत्री का सपना साकार होने की ओर बढ़ सके। मामले में नगर परिषद सीएमओ लालसिंह राठौर का कहना है कि लॉक डाउन की वजह से सर्वे का प्रतिवेदन नहीं लग पाया था, जो अब लग चुका है जल्द ही हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंच सकेगा।

निजी शिक्षण संस्थाओं की बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, थांदला। नगर के समस्त निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक स्थानीय अणु पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। जिसमें सेंट फ्लोरा स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती क्लेमंसी को एसोसिएशन का अध्यक्ष एवं अणु पब्लिक स्कूल के

संचालक प्रदीप गादिया को सर्वानुमति से संघ का सचिव नियुक्त किया गया। उक्त बैठक में संस्कार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर ललित कांकरिया, फ्लोवर लेट से फादर थॉमस, प्राचार्य सिस्टर पेट्रिशिया, मिशन स्कूल से प्राचार्य सिस्टर बेन्सी, हिमालया स्कूल से डायरेक्टर बुरहानुद्दीन, आइडियल स्कूल से विशाल घोड़ावत आदि उपस्थित रहें। उपरोक्त बैठक में सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि आगामी शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शिक्षण शुल्क में कोई वद्धि नहीं की जाएगी। साथ ही आगामी शिक्षा सत्र का संचालन प्रशासन द्वारा निर्देशित नए नियमानुसार किया जाएगा। इस हेतु एसोसिएसन ने पालकगणों से सहयोग की अपेक्षा की है। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। बैठक में आभार अणु पब्लिक स्कूल के प्राचार्य प्रमोद नायरने माना।

हम लोकमान्य पत्रकार है और लोकमान्य ही रहेंगे, आप अधिमान्य हो अच्छी बात है

माही की गूंज, झाबुआ।

एक सच्चे कलम के सिपाही को अधिमान्यता की, नहीं लोकमान्यता की आवश्यकता होती है और हमारी लेखनी के साथ हम लोकमान्य पत्रकार हैं, हमें गर्व है। हमारे पाठकों की विश्वसनीयता अनुसार हमारी कलम निरंतर ऐसे ही चलकर पाठकों के विश्वास पर खरा उतरकर हम सदैव लोकमान्य पत्रकार रहेंगे। बता दें कि, कई ऐसे पत्रकार है जिनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में न कोई उपलब्धि है, न कोई आमजन के हित के लिए पत्रकारिता के माध्यम से कोई मुद्दे उठाए हो या कोई कार्य किया हो, पर जी साहब-जी साहब वाले चापलूसीगिरी कर नेताओं और अधिकारियों के तलवे चाट-चाटकर प्रशासन को गुमराह कर अधिमान्य पत्रकार बन गए और ऐसे ही जी साहब-जी साहब वाले पत्रकारिता में उपलब्धि रखने वाले अधिमान्य पत्रकार, लोकमान्य पत्रकार को जी साहब वाली राजनीति कर अपने अधिमान्यता का रौब झाड़ते हैं।

भाई, आप अधिमान्य पत्रकार बने अच्छी बात है और हमें इससे कोई लेना-देना भी नहीं है कि, आप कैसे अधिमान्य पत्रकार बने। माही की गूंज पोर्टल पर जिले की भाजपाई राजनीति व हत्या जैसे दाग लगे प्रशासनिक अधिकारी रिटायरमेंट के साथ ही आयातित कांग्रेसियों की उंगली पकड़, भाजपा का पल्ला पकड़ा और विधायक से सांसद कैसे बने व भाजपा संगठन के सिपाहियों को दरकिनार कर आयातित लोगों को पदाधिकारी कैसे बनाया और भाजपा में ही रहकर भाजपा से अलग अपना संगठन खड़ा करने वाले गुमान की गुमानियत एवं भाजपा संगठन से ही छनकर आ रही जानकारी अनुसार भाजपाई राजनीतिक समीकरण एवं पूर्व विधायक निर्मला भूरिया को कैसे दरकिनार करने की राजनीति भाजपा में चल रही है, को प्रकाशित किया जा रहा है।

जिस पर मंगलवार को चौथा भाजपा राजनीति समीकरण प्रकाशित होने के बाद सांसद से उपकृत रिश्तेदार व पेट्रोल पंप संचालक जी साहब की राजनीति व पत्रकारिता के नाम पर बना अधिमान्य पत्रकार जिसने ही ऐसे कई कार्य किए जिससे सांसद की छवि बनने की बजाएं बिगाड़ने का ही कार्य किया है। पर वो भी ऐसा बौखलाया कि, उसने माही की गूंज कार्यालय में मंगलवार को 9425101077 से फोन लगाकर गूंज पोर्टल एवं गूंज समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर बोखलाहट प्रदर्शित कर रहा था। उक्त व्यक्ति की बात से लग रहा था कि, हमारी लेखनी का असर झाबुआ से लेकर भोपाल वं भोपाल से लेकर दिल्ली तक कर रहा है।

पेट्रोल पंप पर अपने अखबार का बोर्ड लगाने वाला जिस समाचार पत्र का नाम सिर्फ उक्त पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल भरते समय ही देखा जाता है। वह अधिमान्य पत्रकार फोन लगाकर माही की गूंज कार्यालय में कहता है कि, आप जो समाचार मोर्चा खोल छाप रहे हो वो सही नहीं है, वो मेरे मामाजी हैं। रोज न्यूज आ रही है निर्मला वो करती है, निर्मला ये करती है, मैं भी 2011 व 2004 से पत्रकार हूं आप अगर ऐसा कर रहे हो तो मुझे भी सक्रिय होना पड़ेगा। गूंज कार्यालय से जवाब मिला, राजनीतिक समीकरण है वो छप रहे है, इसमें मोर्चे की क्या बात है? जिस पर धमकाने के लहजें में समीकरण पर ही मिलेंगे अधिमान्य पत्रकार कहते हुए कहने लगा, अब हम भी समाचार में ही मिलेंगे।

जब गूंज में उक्त फोन करने की जानकारी निकाली तो पेट्रोल पंप पर कुछ जी साहब-जी साहब करने वाले चापलूसों ने भानेजलाल को उकसाया और भानेज ने मामा प्रेम के साथ अपनत्व जताकर चापलूसों के सामने समाचार प्रकाशित न हो की नियत से, एवं अपना दबदबा बनाने हेतु व मामा से वाहवाही लूटने के लिए फोन लगाया, पर भाई अपने मामा से जाकर पूछो उनका कहना है जब तक हमारे बारे में हमारी कमियां कोई नहीं बताएगा तो हम हमारी कमियों को नहीं सुधार पाएंगे। आपके मामा के पास जी साहब-जी साहब करने वाले हमको छोड़कर कई चापलूसियों की भर्ती है। उसमें हमारी भर्ती कभी ना करें। माही की गूंज की लेखनी पाठकों की विश्वसनीयता के साथ सदैव चलती रहेगी, इसलिए हम हमारी लेखनी और हमारी मित्रता एवं संबंधों को सदैव पृथक रखते हैं। सिर्फहम आपसे यही कहना चाहेंगे कि, इस प्रकार से धमकाकर आप हमें हमारी लेखनी को रोकने का कभी प्रयास न करें, अगर आपकी सरकार व सत्ता है, तो हम भी हमारी कलम की लेखनी के साथ एक लोकमान्य पत्रकार है। आप अपने व अपने मामा के प्रभाव से हमारी हत्या करवाने जैसे प्रयास भी करवा दें, तो भी हम हमारी अंतिम सांस तक भी हमारी कलम आमजन के हित के लिए चलाते रहेंगे।

स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बुधवार को सुलूर एयरबेस में भारतीय वायु सेना की 18 स्क्वाड्रन श्फ्लाइंग बुलेटश् का परिचालन शुरू किया। यह स्क्वाड्रन एलसीए तेजस विमान से लैस होगी। तेजस को उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की यह दूसरी स्क्वाड्रन है।

एयर चीफमार्शल आरकेएस भदौरिया ने आज सुबह कोयम्बटूर के पास एयरफोर्स स्टेशन सलूर में 45 स्क्वाड्रन के साथ एलसीए तेजस फाइटर के सिंगल कॉकपिट में उड़ान भरी। वायु सेना प्रमुख ने इसी के साथ आज स्वदेशी तेजस की वायु सेना में दूसरी स्क्वाड्रन का पूर्ण परिचालन वायु सेना स्टेशन, सुलूर से शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को एचएएल से खरीदा है। इसके लिए नवंबर 2016 में भारतीय वायुसेना ने 50,025 करोड़ रुपये में 83 तेजस मार्क-1 ए की खरीदी को मंजूरी दी थी। इस समझौते पर आखिरी समझौता लगभग 40 हजार करोड़ रुपये में हुआ है।

तेजस एक स्वदेशी चौथी पीढ़ी का बिना पूंछ वाला कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। यह विमान फ्लाई-बाय-वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एकीकृत डिजिटल एवियोनिक्स, मल्टीमॉड रडार से लैस है। यह चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के समूह में सबसे हल्का और सबसे छोटा है। भारत में बने एलसीए तेजस को 21 फरवरी, 2019 को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला और औपचारिक तौर पर तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया। तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बेंगलुरु में हुए एयरो इंडिया-2019 समारोह के दौरान छोटी सी उड़ान भरके स्वदेशी लड़ाकू विमान का निरीक्षण किया था। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी 19 सितम्बर, 2019 को बेंगलुरु में स्वदेशी तकनीक पर विकसित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भर चुके हैं।

इस 18 स्क्वॉड्रन का गठन 15 अप्रैल 1965 को आदर्श वाक्य श्तीव्र और निर्भयश् यानी श्स्विफ्ट एंड फियरलेसश् के साथ किया गया था। एयरफोर्स की यह स्क्वॉड्रन 15 अप्रैल, 2016 से पहले मिग 27 विमान उड़ा रही थी। इस स्क्वॉड्रन को इस साल 01 अप्रैल को सुलूर में पुनर्जीवित किया गया था। इस स्क्वॉड्रन ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्क्वॉड्रन के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार श्परमवीर चक्रश् से अलंकृत किया गया था। इस स्क्वॉड्रन ने श्रीनगर में श्डिफेंडर्स ऑफ कश्मीर वैलीश् का पहला ग्राउंड बनाया और इसे संचालित किया।

बांग्लादेशी अजीत राय के कारनामें का एक और खुलासा

फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर बांग्लादेशी समधी परिवार का कराया पंजीयन

पहले एक माह तक लगाए चक्कर बाद में दूसरी पंचायत से बनवाया फर्जी प्रमाण-पत्र

माही की गूंज। संजय भटेवरा

सोशल मीडिया पर पुलिस डिपार्टमेंट, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, स्पेशल ऑफिसर लिखी चश्मे के साथ यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर से एडिट कर एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल कर जेंटलमैन बनने वाला संविधान की हर लाइन को क्रॉस कर भारतीय संविधान को धुमिल व पूरी व्यवस्थाओं को ही हास्यप्रद स्थिति में लाकर खड़ा करने वाले अजीत राय की कारस्तानियों की माही की गूंज पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है।

बता दे कि, अजीत राय की बेटी ब्यूटी का विवाह बांग्लादेश के ही रहवासी तुषार पिता किरन मंडल के पुत्र शामल से किया। जिसके बाद बांग्लादेशी अजीत राय विवाह के बाद बांग्लादेशी जमाई को भी कुछ समय के लिए खवासा ले आया। हमने पहले भी खुलासा किया था कि, जो बांग्लादेश में रहकर कभी खवासा ही नहीं आया, उनका नाम भी खवासा पंचायत में कुछ प्रलोभन के साथ पंजीयन करवाकर बांग्लादेशी को खवासा का मूल निवासी बनाने के साथ ही भारतीय मूल का रहवासी बना दिया। कुछ इसी तरह बांग्लादेश से दलाल के मार्फत से शामल पिता तुषार मंडल भी आया था। उसी बांग्लादेशी शामल मंडल के साथ, रतलाम निवासी बांग्लादेशी अजीत राय के साथी दीपू राय के घर पर छोटे रूप में गिनती के मेहमानों की उपस्थिति में अजीत राय ने बेटी की शादी कर दी। बताया जा रहा है कि, बेटी ने भी ऐसी कोई एक कारस्तानी कर दी थी, जिसके कारण छोटे रूप में रतलाम में 40-50 मेहमानों की उपस्थिति में बेटी की शादी करना पड़ी, लेकिन खवासा में आकर मोहल्ले एवं गांव वालों को बेटी की शादी पश्चिम बंगाल में करना बताया।

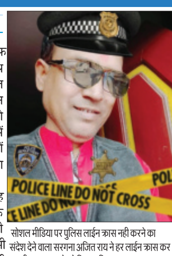

सोशल मीडिया पर पुलिस लाईन क्रास नही करने का संदेश देने वाला सरगना अजित राय ने हर लाईन क्रास कर भारतीय व्यवस्थाओ को किया धुमिल।

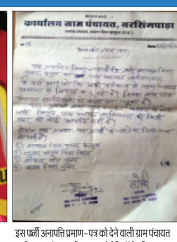

इस फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को देने वाली ग्राम पंचायत नरसिंगपाडा के पास ही इसका कोई रिकॉर्ड नहीं।

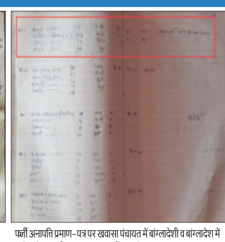

फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर खवासा पंचायत में बांग्लादेशी व बांग्लादेश में रहने वाले का पंजीयन कर बनाया फर्जी दस्तावेज।

गूंज ने जमाई शामल व परिवार की पड़ताल में माता-पिता, भाई अभी भी बांग्लादेश में, पर नाम खवासा पंचायत में

सरगना अजीत राय के जमाई शामल की भी पूरी पड़ताल की तो, गूंज के सामने विशेष सूत्रों के माध्यम से बड़ा मामला सामने आया। शामल बांग्लादेश के दलाल के माध्यम से ही चोर रास्ते से भारत आया। सूत्रों अनुसार जानकारी मिली कि, सन् 2010-11 में शामल को अजीत राय ने अपने फर्जी क्लीनिक पर रखकर फर्जी डॉक्टरी का काम सिखाया। कुछ अनबन होने पर अजीत राय ने अपने यहां से रवानगी दे दी। तब भामल के गौतम राय के फर्जी क्लीनिक पर 2012-13 में फर्जी डॉक्टरी का ज्ञान दिया। जिसके बाद करीब 1 वर्ष से अधिक गुजरात में किसी अपने बांग्लादेशी के यहां शामल ने फर्जी ट्रेनिंग अर्जित की। जिसके बाद रतलाम निवासी दीपू राय जिसका फर्जी क्लीनिक रतलाम जिले के बाजना तहसील के एक ग्राम में स्थित है, पर कंपाउंडर की परिभाषा देकर कार्य कर रहा था कि, अजीत राय के एक बांग्लादेशी वर्तमान में बाजना निवासी तपन राय से बेटी की शादी के लिए संपर्क किया तो, तपन ने अजीत को शामल का नाम सुझाया। जिसके बाद कुछ दिनों में ही बेटी की शादी शामल के साथ कर जमाई बना लिया। शामल को बेटी के साथ घर ले आया। घर लाते ही कुछ दिनों बाद सरगना अजीत राय अपनी कारस्तानियों के साथ खवासा ग्राम पंचायत में शामल के साथ ही उसके माता-पिता व छोटे भाई जो कि, बांग्लादेश में ही निवासरत थे, सभी के नाम पंचायत में पंजीयन करवाने को लेकर पंचायत के चक्कर काटने लगा। पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत में परिवर्तन होने पर सचिव ने जहां पहले से निवासरत् थे, वहां का अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा। लेकिन वह अनापत्ति प्रमाण-पत्र काफी समय तक नहीं दे पाया। जिसके बाद खवासा की समीपस्थ ग्राम पंचायत नरसिंगपड़ा के सरपंच पति व सचिव से संपर्क किया। उनको खवासा में अजीत राय के मकान में शामल के साथ उसके माता-पिता व भाई को रहना बताकर हाथ-पैर जोड़ व नगदी भेंट कर फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र नरसिंगपाड़ा पंचायत से बनवा लिया।

ग्राम पंचायत नरसिंगपाड़ा ने 22 फरवरी 2016 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र क्रमांक 19 दर्शाकर प्रमाणित किया कि, शामल पिता तुषार मंतुल (मंडल की जगह मंतुल) का ग्राम पंचायत नरसिंगपाड़ा में दर्ज था, जो वर्तमान में खवासा में रह रहे हैं व ग्राम पंचायत नरसिंगपड़ा से नाम काटा जा चुका है। खवासा में नाम जोड़ने पर नरसिंगपाडा पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ प्रमाण-पत्र में नीचे शामल उसके पिता तुषार, मां नमिता व भाई बादल का नाम दर्शा दिया गया।

उसी दिनांक 22 फरवरी 2016 को ही ग्राम पंचायत खवासा के पंजीयन रजिस्टर क्रमांक 839 पर दर्ज कर हाथों-हाथ उसी दिनांक को ही कूपन जारी कर दिया। जिसके बाद शामल को रावटी में फर्जी क्लीनिक खुलवाया। वहां दुकानदारी नहीं चली तो रतलाम के शिवगढ़ में फर्जी क्लिनिक खुलवाया, जो वर्तमान में भी शिवगढ़ में ही रह कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर चांदी काट रहा है।

तो वहीं शामल एवं पत्नी ब्यूटी का नाम खवासा की नामावली में क्रं. 2312-2313 पर आज भी होकर खवासा पंचायत में उसके माता-पिता के साथ भाई बादल का नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज होकर राशन कार्ड में भी है।

जबकि गूंज ने 30 अप्रैल के अंक में 'घुसपैठिये अजित राय ने बांग्लादेशी समधन की क्वॉरेंटान के समय छुपाई पहचान', 'बांग्लादेशी घुसपैठिये ने आखिर कैसे बनाए फर्जी दस्तावेज? यह है जांच का विषय' शीर्षक के साथ प्रकाशित कर खुलासा किया था कि, क्वॉरेंटाइन के समय समधन नमिता बांग्लादेश के पासपोर्ट से खवासा आई और अजीत राय के क्वारंटाइन के समय घर में रहते हुए उसकी पहचान छुपाई। वहीं आज भी लॉकडाउन के कारण बांग्लादेश से आई समधन अजित राय के संरक्षण में ही है। ये भी साफ है कि, शामल के माता-पिता व भाई बांग्लादेश में ही निवासरत है, जो भारत में कभी चोर के रास्ते से तो कभी बांग्लादेश के पासपोर्ट के माध्यम से आते हैं तो बांग्लादेशी बेटा कैसे भारतीय हो गया? और जो बांग्लादेश के पासपोर्ट से अजीत राय के समधी उर्फशामल के माता-पिता भारत आते हैं वो झाबुआ जिले की नरसिंगपाड़ा पंचायत से कैसे फर्जी प्रमाण-पत्र बना कर खवासा पंचायत में अपना नाम पंजीयन करवा कर भारतीय मूल के बन फर्जी दस्तावेज कैसे बना लिए? यह जांच का विषय है।

जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर जांच करवा कर अजीत राय की तरह प्रदेश में जिन्होंने भी भारतीय मूल की व्यवस्था एवं संविधान को हाशिये पर धकेल कर उसे धूमिल करने का प्रयास किया है उनके विरुद्ध जांच करवा कर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए।

अब देखते हैं ग्राम पंचायत नरसिंगपाडा व ग्राम पंचायत खवासा अजीत राय के विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है? या जिस तरह से फर्जी पंजीयन के लिए नगद नारायण लिया। गूंज की लेखनी के बाद अपनी कीमत बढ़ाकर अभी भी सरगना अजित राय के साथ उन सभी को जो बांग्लादेशी होकर या बांग्लादेश में रहकर यहां के निवासी बन गए है, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे? नरसिंगपाड़ा पंचायत से जब जानकारी ली तो पंचायत में किसी भी रिकॉर्ड में शामल एवं परिवार का नाम दर्ज ही नहीं है। 22 फरवरी 2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। जिसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं दुसरी ओर ग्राम पंचायत खवासा के पास, नरसिंगपाड़ा का दिया हुआ फर्जी प्रमाण-पत्र रिकॉर्ड में बता रहा है।

तुम्हारी मजबूरी तुम्हें ले जाएगी और तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मील मंसूरी

कोरोना महामारी ने एक ऐसी कहानी गढ़ दी है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर सदियों याद की जाती रहेगी। पूरे विश्व को इस महामारी ने अपनी जद में लिया। लाखों जानें अब तक इससे जा चुकी है। इस महामारी ने भारत में भी अपने पैर पसारे और अब तक यह बढ़ती ही चली जा रही है। हालात इतने बेकाबू होते जा रहे है कि देश में 6 हजार से ज्यादा मामले रोजाना निकलने लगे है। सरकारें और तंत्र एक दम लाचार या बेपरवाह नजर आने लगे है।

महामारी को देखते हुए देश में लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन को देश में करीब 60 दिन से अधिक हो चुके है। किसी ने भी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि पहले चरण में 21 दिनों के लॉकडाउन से शुरू होकर हम लॉकडाउन के चौथे चरण तक पहुंच जाएंगे। कई बुद्धिजीवी लोगों का यह मानना है कि महामारी से बचने के लिए हमारे पास मात्र लॉकडाउन ही एक रास्ता था। इस 60 दिन से अधिक के लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को लगभग चकनाचूर कर दिया है। बड़े-बड़े उद्योगों से लेकर छोटे-छोटे उद्योगों, कारखानों तक में सन्नाटा पसर गया।

लॉकडाउन के इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो वो है मजदूर वर्ग। काम-काज बंद होने और लॉकडाउन के चलते जो जहां था वहीं फंस गया। जो कमाया था वह पहले चरण के 21 दिनी लॉकडाउन में खत्म हो गया और उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वह कोरोना महामारी के साथ मजदूरों के पलायन, परिवार के साथ हजारों किलो मीटर के पैदल सफर, पैरों में पड़े छालों, भूखमरी, दुर्घटनाओं में मौतों और उसके बाद सरकार के रवैये को देखते हुए हिंसक, विद्रोह और भूख मिटाने के लिए लूटमार की थी, जो आज तक भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। येन-केन प्रकारेण मजदूर लोग अपने घरों तक किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहते है। कई पहुंच चुके है। कई रास्ते में है और संघर्ष कर रहे है। सरकारी इंतजाम इन मजदूरों के लिए बोने साबित हुए। करोड़ों करोड़ मजदूर इस प्रण के साथ पैदल ही अपने घर पहुंच गया कि अब कभी शहर की ओर लौटकर नहीं आएगा।

बात अगर सिर्फआदिवासी बाहुल जिले झाबुआ की करें तो यह माना जाता है कि यहां की लगभग 70 फीसदी आबादी मजदूरी के लिए अन्य राज्यों में पलायन करती है। इनके पलायन के कारण भी बहुत है। पहला बड़ा कारण जो माना जाता है वह मजदूरी का दाम है। जो उन्हें अपने प्रदेश से कई अधिक अन्य प्रदेशों में मिलता है। दूसरा यह भी है कि मध्यप्रदेश की अपेक्षा अन्य प्रदेशों में रोजगार की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। मतलब बिल्कुल सीधा-सीधा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाई और जहां सरकार बहुत थोड़ रोजगार उपलब्ध करा पाई है, वहां मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं दे पाई।

अब जबकि कोरोना महामारी के चलते जिले की पलायन पर गई 70 फीसदी आबादी वापस जिले में आ चुकी है, तो बेरोजगारी की दर बढ़ना ही है और इस परिस्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन अब भी ऊंघता ही नजर आ रहा है। सिर्फ मनरेगा ही एक मात्र रास्ता जिला प्रशासन के पास है। जिससे मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। हालात कुछ ऐसे है कि जिले की कुल आबादी लगभग 11 लाख है, इनमें से लगभग 7 लाख ग्रामीण मजदूर पलायन करते है जो जिले की आबादी का लगभग 70 फीसदी है। अब यह 70 फीसदी आबादी जो पलायन पर गई थी वह लौट आई है और उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न रोजगार का ही है। जिला प्रशासन ने इनके लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत कई काम शुरू तो किए, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहे है। झाबुआ जिले में लगभग 70 हजार मजदूरों को ही अब तक रोजगार मिल पाया है, जबकि पलायन से लौटने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। उस पर भी सीतम यह कि मजदूरों के हक में भ्रष्टों का हिस्सा अलग। इंजीनियरों से लेकर ठेकेदारों तक ने इनके हक में सेंधमारी शुरू कर दी है। मनरेगा के कर्यों में हो रहा मशीनों का उपयोग इस बात का गवाह है। आए दिन अखबारों व टीवी चौनलों पर इस तरह की खबरें आम हो रही है, मगर किसी को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा।

हालात को देखते हुए यह अंदाजा लगाना मुश्किल तो बिलकुल भी नहीं है कि सरकार या जिला प्रशासन लौटे इन मजदूर ग्रामीणों को भरपूर रोजगार उपलब्ध करा पाएगा या नहीं। भले ही मुख्यमंत्री टीवी पर आकर रोजगार देने की बात कहते हों लेकिन जमीनी हकीकत बिलकुल इसके विपरीत है। कुल मिलाकर हालात पहले जो थे वह अब भी है यानि ढाक के वहीं तीन पात। अब इस स्थिति में यह ग्रामीण मजदूर जिले में बेरोजगार होकर कितने दिन और रह पाएंगे यह यक्ष प्रश्न है। क्योंकि अब केंद्र और प्रदेश सरकारों ने भी लॉकडाउन में ढील दी है और उद्योगों को शुरू करने के निर्देश भी दिए है। मगर इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूर अपने घर लौट आए है तो उद्योगों का चालू होना कितना सच माना जाना चाहिए। इधर ग्रामीण मजदूरों को अगर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो इनके यहां भी भूखे मरने की नौबत खड़ी हो जाएगी और यही मजबूरी इन ग्रामीण मजदूरों को वापस पलायन करने पर मजबूर करेगी।

तो मजदूर वर्ग भी यह जान ले कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। क्योंकि तुम्हारे प्रदेशों की सरकार तुम्हे रोजगार नहीं दे सकती है और अन्य प्रदेशों की सरकार रोजगार तो देगी मगर सुरक्षा नहीं। तुम्हारी स्थिति बिलकुल वैसी है जैसे एक तरफकुआं तो दूसरी तरफ खाई। या तो अपने प्रदेश में बेरोजगारी का दंश झेलकर भूखे मर जाओ या अन्य प्रदेशों में जाकर महामारी, बीमारी, कारखानों की जहरीली गैसों या उद्योगों के जरिए होने वाली बिमारियों से मर जाओ। मगर फिर भी तुम्हारी मजबूरी तुम्हें वापस पलायन पर ले जाएगी और तुम्हे जाना ही पड़ेगा।

भट्टी की तरह धधक रहा अंचल, नवतपा का असर, पारा 43 पर पहुंचा

माही की गूंज, झाबुआ। नवतपा की शुरूआत सोमवार से हो चुकी है। नौ दिनों तक अब क्षेत्र में अधिक गर्मी का अहसास बना रहेगा। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिन में तो धूप के तेवर तीखे रहते है, लेकिन रात में भी लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री का उछाल आकर यह 28 पर आ गया है। उधर अधिकतम तापमान 43 डिग्री के करीब जमा हुआ है। दिन में तेज धूप व गर्मी के कारण चौक-चौराहे सूने पड़े रहते हैं। सोमवार से 2 जून तक लगातार गर्मी बनी रहेगी। इन दिनों नौतपा चलने से और अधिक गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग अधिकतम तापमान 44 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जाने की संभावना पहले ही व्यक्त कर चुका हैं। रविवार की रात न्यूनतम तापमान 26.02 डिग्री सेल्सियस था, जो सोमवार की रात को 28 डिग्री तक पहुंच गया। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दिन के साथ अब तो रात में भी लोगों को गर्मी से चौन नहीं मिल पा रहा है। दिन में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन कर रहे है।

कम रहती है भीड़भाड़

शहर में इन दिनों लॉकडाउन से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक छूट दी गई है। 11 बजे के बाद शहर में कम ही चहल-पहल दिखाई देती है। दोपहर आते-आते तो बाजार में नाममात्र का आवागमन दिखाई देता है। दोपहर में पड़ रही तेज गर्मी का असर यह है कि चौक -चौराहे सूने पड़े रहते है। लोग गर्मी से बचने के लिए फलों का सहारा ले रहे है। तरबूज, शक्कर बट्टी, मौसंबी, पाइन एपल आदि फलों की बिक्री जमकर हो रही है। चौक-चौराहों पर लोग अधिकतर फल खरीदते नजर आते है। आगामी दिनों में भी इसी तरह गर्मी का अहसास बने रहने की संभावना है।

लू के थपेड़ों ने किया परेशान

दोपहर में गर्मी का अहसास अधिक हो जाता है। 11 बजे बाद से ही अब तो लू के थपेड़े लगना शुरू हो जाते है, जो देर शाम तक चलते रहते है। सबसे अधिक दिक्कत पैदल व दो पहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। लोग अपने शरीर को ढंककर निकलते है। मौसम का सीधा असर बच्चों व बुजुर्गों पर अधिक पड़ रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422